भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA
Corporate Communications Directorate

BUSINESS STANDARD DELHI 8 NOVEMBER 2024

नोएडा हवाई अड्डे में टाटा पावर करेगी निवेश

टाटा पावर नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (एनआईए) को स्वच्छ ऊर्जा की आपूर्ति के लिए सौर और पवन ऊर्जा क्षमताओं और संबंधित बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 550 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। टाटा पावर ने नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा परियोजना के साथ दो बिजली खरीद समझौतों (पीपीए) पर हस्ताक्षर किए हैं। कंपनी ने बयान में कहा, 'टाटा पावर ने नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (एनआईए) के साथ नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण के लिए रणनीतिक साझेदारी की है।' *भाषा*

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA
Corporate Communications Directorate

BUSINESS STANDARD DELHI 8 NOVEMBER 2024

Tata Power to invest ₹550 cr to develop Noida Airport infra

Tata Power on Thursday said it would invest ₹550 crore for development of infrastructure to cater to power purchase agreements signed with Noida International Airport (NIA). Tata Power would make this investment in solar and wind power supply. It would also invest in development of essential dry utilities and smart energy infrastructure development of critical dry utilities, including essential electrical infrastructure, and would provide operation and maintenance services for this infrastructure over a 25-year period.

BS REPORTER

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA
Corporate Communications Directorate

DESHBANDHU DELHI 8 NOVEMBER 2024

एयरपोर्ट के पास अमेरिकन सिटी

- दो से तीन अरब डॉलर का पांच से छह साल में निवेश
- नोएडा एयरपोर्ट के पास 1200 एकड़ में बसेगी अमेरिकन सिटी
- अमेरिका में सत्ता परिवर्तन के बाद अमेरिकन सिटी के जल्द परवान चढ़ने की संभावना

ग्रेटर नोएडा, 7 नवम्बर (देशबन्धु)। अमेरिका में सत्ता परिवर्तन के बाद डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद यमुना एक्सप्रेस वे प्राधिकरण क्षेत्र के नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास अमेरिकन सिटी विकसित करने का रास्ता अब जल्द साफ होने की उम्मीद है। एयरपोर्ट के अलामो और फीनिक्स की तर्ज पर अमेरिकन सिटी विकसित किया जाएगा।

नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास प्रस्तावित 'अमेरिकन सिटी' में उद्योग, आवास, शैक्षिक केंद्र और मनोरंजन सुविधाएं शामिल होंगी। अमेरिकी कंसल्टेंसी फर्म ब्लू स्काई वैंटेज, जिसने अपने विजन डॉक्यूमेंट में 1,200 एकड़ जमीन का अनुरोध किया है, ने 10,000 से अधिक प्रत्यक्ष नौकरियां पैदा करने और 4,000 लक्जरी आवास इकाइयों को विकसित करने की योजना की घोषणा की है, साथ ही अमेरिकन बिजनेस लीडरशिप स्कूल के लिए 3,000-छात्र केंद्र भी बनाया है। प्री-के से 12वीं कक्षा तक फैला हुआ। कंपनी की योजना अपने निवेशकों के माध्यम से अगले पांच से छह वर्षों में 2-4 बिलियन डॉलर के बीच निवेश करने की है।

एक आत्मनिर्भर समुदाय के रूप में कल्पना की गई, अमेरिकन सिटी में एआई, सेमीकंडक्टर, प्रौद्योगिकी, विनिर्माण, स्वास्थ्य देखभाल, खुदरा, आतिथ्य, प्रबंधन और अन्य प्रमुख उद्योगों पर

की गई, अमेरिकन सिटी में एआई, सेमीकंडक्टर, प्रौद्योगिकी, विनिर्माण, स्वास्थ्य देखभाल, खुदरा, आतिथ्य, प्रबंधन और अन्य प्रमुख उद्योगों पर

केंद्रित औद्योगिक सुविधाएं शामिल होंगी। परिवहन, लॉजिस्टिक्स और निर्माण जैसे सहायक क्षेत्रों में कई अप्रत्यक्ष नौकरियां पैदा होंगी। अमेरिकन लीडरशिप एकेडमी इंटरनेशनल (एएलएआई) नामक शैक्षणिक केंद्र उच्च गुणवत्ता वाले सीखने के अवसर प्रदान करेगा और छात्रों को एक संपन्न पेशेवर पारिस्थितिकी तंत्र से जोड़ेगा।

अमेरिका स्थित कंसल्टेंसी फर्म, जो अमेरिकी कंपनियों को नए बाजारों में विस्तार करने में सहायता करती है, ने तीन प्रमुख विकासों के लिए जमीन मांगी हैरू अमेरिकन सिटी के लिए 1,000 एकड़, एएलएआई के लिए 100 एकड़ और सेक्टर 22ई में एक मनोरंजन जिला, और मिश्रित उपयोग के लिए 100 एकड़ जमीन। सेक्टर 22डी में आवासीय विकास। ये परियोजनाएं भारत के निवासियों के लिए असाधारण डिजाइन, कनेक्टिविटी, मनोरंजन, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, स्थिरता और नौकरी के अवसरों को एकीकृत करते हुए उत्तर प्रदेश की समृद्ध और ऐतिहासिक संस्कृति का सम्मान करेंगी। ब्लू स्काई के सीईओ जैक मैक्केन ने लिखा, लक्ष्य जीवंत जीवन शैली विकल्पों और शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, मनोरंजन, खुदरा और समुदाय और जेवर हवाई अड्डे से कनेक्टिविटी जैसी आवश्यक सुविधाओं के साथ पूरक व्यवसाय के

देखभाल, मनोरंजन, खुदरा और समुदाय और जेवर हवाई अड्डे से कनेक्टिविटी जैसी आवश्यक सुविधाओं के साथ पूरक व्यवसाय के

अवसरों के साथ जीवन के लिए एक नया मानक स्थापित करना है। जेवर हवाई अड्डे के पास प्रस्तावित परियोजनाएं नोएडा और उत्तर प्रदेश के भविष्य में एक दूरदर्शी निवेश का प्रतिनिधित्व करती हैं। महत्वपूर्ण आर्थिक, रोजगार और सांस्कृतिक लाभ प्रदान करने के लिए डिजाइन किए गए, उनका लक्ष्य नोएडा को मनोरंजन और संस्कृति के लिए एक प्रमुख गंतव्य बनाना है। ब्लू स्काई वैंटेज इस दृष्टिकोण को साकार करने, एक गतिशील, जीवंत स्थान बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे स्थानीय समुदाय और अंतरराष्ट्रीय आगंतुकों दोनों को लाभ होगा, अगले पांच से छह वर्षों में 2-4 बिलियन के बीच नियोजित निवेश करेगा।

वर्तमान में, यीडा ने सेक्टर 22 ई में के लिए 100 एकड़ भूमि के लिए आशय पत्र जारी किया है, जबकि अन्य घटक विचाराधीन हैं। एएलएआइ ने औद्योगिक विकास के लिए नामित सेक्टर 5 और 5ए से सेक्टर 8 डी में 1,000 एकड़ भूमि के प्रस्ताव को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है।

यीडा के सीईओ अरुण वीर सिंह ने कहा कि सरकार से अंतिम मंजूरी मिलने के बाद हम जल्द ही सेक्टर 8 के लिए सीधी जमीन खरीद शुरू करेंगे। विजन दस्तावेज के अनुसार, एएलएआइ को दो चरणों में विकसित किया जाएगा। परिसर में गणित, भौतिक विज्ञान, प्रौद्योगिकी, भाषा कला, इतिहास, नागरिक शास्त्र और शारीरिक शिक्षा में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी। शिक्षा के लिए समग्र दृष्टिकोण पर जोर देते हुए, परिसर ललित और प्रदर्शन कला, खेल और उन्नत तकनीकी और व्यावसायिक अध्ययन में विविध ऐच्छिक के लिए स्थान और सुविधाएं भी प्रदान करेगा। एएलआई की योजना भारत और विदेश से शीर्ष प्रतिभाओं की भर्ती करने की है। संकाय और अतिथि विद्वानों

सुविधाएं भी प्रदान करेगा। एएलआई की योजना भारत और विदेश से शीर्ष प्रतिभाओं की भर्ती करने की है। संकाय और अतिथि विद्वानों

का समर्थन करना। अमेरिकन लीडरशिप एकेडमी इंटरनेशनल चरण एक की योजना में एक कॉन्सर्ट हॉल और प्रदर्शन कला परिसर, एक जलीय केंद्र, एक घुड़सवारी केंद्र, एक इनडोर खेल परिसर, आउटडोर खेल सुविधाएं और प्रमुख भारतीय और अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ साझेदारी में एक क्रिकेट अकादमी भी शामिल है। एक अत्याधुनिक एथलेटिक प्रदर्शन केंद्र पोषण, फिटनेस और स्वास्थ्य के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करेगा, जो प्रशिक्षण के लिए राज्य, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के एथलीटों के लिए खुला है। इसके अतिरिक्त, 150 एकड़ का गोल्फ कोर्स भारत की प्रमुख गोल्फ प्रशिक्षण सुविधाओं में से एक प्रदान करेगा। चरण 2 में भारत में उच्च शिक्षा और अनुसंधान कार्यक्रम स्थापित करने में रुचि रखने वाले विश्वविद्यालय भागीदारी के लिए सुविधाएं शामिल करने का अनुमान है। दस्तावेज में कहा गया है कि एएलआई ने पहले ही कई विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से महत्वपूर्ण रुचि प्राप्त कर ली है। एक प्रमुख मनोरंजन केंद्र के रूप में स्थापित, 1000 एकड़ में अमेरिकन सिटी के विकास से घरेलू और अंतरराष्ट्रीय निवेशकों को आकर्षित करने की उम्मीद है, जिससे नोएडा और जेवर को व्यापार और पर्यटन के लिए प्रमुख स्थानों के रूप में बढ़ावा मिलेगा।

विभिन्न आवास उत्पादों की कल्पना की गई है, जिनमें कार्यबल आवास, पारिवारिक आवास, हाई-एंड गोल्फ सामुदायिक आवास से लेकर सेवानिवृत्ति और वरिष्ठ आवास शामिल हैं। प्रस्तावित मिश्रित उपयोग आवासीय क्षेत्र, जिसका नाम - इमेजिन यूपी - है, वैश्विक दर्शकों के लिए डिजाइन किया गया 100 एकड़ का मेगा-विकास होगा। इसमें तीन एकड़ का केंद्रीय पार्क और भोजन, मनोरंजन और खुदरा अनुभवों के

लिए डिजाइन किया गया 100 एकड़ का मेगा-विकास होगा। इसमें तीन एकड़ का केंद्रीय पार्क और भोजन, मनोरंजन और खुदरा अनुभवों के

लिए सामुदायिक सभा स्थान होगा, जो एक उच्च-स्तरीय अमेरिकी किराना स्टोर द्वारा संचालित होगा। नियमित सांस्कृतिक कार्यक्रमों, त्योहारों और प्रदर्शनियों की मेजबानी करके, आवासीय क्षेत्र भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता का जश्न मनाएगा। यह स्थानीय कलाकारों, कलाकारों और कारीगरों के लिए एक मंच प्रदान करेगा, जिससे समुदाय के भीतर सांस्कृतिक आदान-प्रदान और कलात्मक अभिव्यक्ति को बढ़ावा मिलेगा।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA
Corporate Communications Directorate

DESHBANDHU DELHI 8 NOVEMBER 2024

एयरपोर्ट के पास सौर और पवन ऊर्जा में टाटा करेगी 550 करोड़ का निवेश

ग्रेटर नोएडा, 7 नवम्बर (देशबन्धु)। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास टाटा कंपनी सौर और पवन ऊर्जा के उत्पादन पर 550 करोड़ रूपए खर्च करेगी। भारत के विमानन क्षेत्र के भीतर स्थायी बुनियादी ढांचे के विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम, टाटा पावर, भारत की सबसे बड़ी एकीकृत बिजली कंपनियों में से एक है, और उसने नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (एनआईए) के साथ नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण के लिए एक रणनीतिक साझेदारी किया है। पवन और सौर ऊर्जा आपूर्ति से संबंधित दो बिजली खरीद समझौतों (पीपीए) पर नई दिल्ली में टाटा पावर के अध्यक्ष-पारेषण और वितरण संजय बंगा की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए। दीपेश नंदा, सीईओ और एमडी, टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेडय तरुण कटियार, सीईओ, टाटा पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेडय क्रिस्टोफ श्नेलमैन, सीईओ, नोएडा अंतराष्ट्रीय हवाई अड्डा निकोलस शेंक, सीडीओ, नोएडा अंतराष्ट्रीय हवाई अड्डा और दोनों कंपनियों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

■ टाटा एनर्जी के साथ यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने किया समझौता हस्ताक्षर

टाटा पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड (टीपीटीसीएल) इस साझेदारी में सबसे आगे होगी, संपूर्ण नवीकरणीय ऊर्जा पोर्टफोलियो इंटरफेस का प्रबंधन करेगी, और यह सुनिश्चित करेगी कि एनआईए की स्वच्छ ऊर्जा जरूरतों को एक व्यापक पावर खरीद समझौते (पीपीए) के माध्यम से पूरा किया जाए। इस व्यवस्था के तहत, टीपीटीसीएल टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड (टीपीआरईएल) की सुरक्षित संपत्तियों के साथ, एनआईए के लिए 10.8 मेगावाट पवन ऊर्जा की आपूर्ति करेगी। टीपीआरईएल हवाई अड्डे की समग्र ऊर्जा जरूरतों में योगदान देने के लिए 13 मेगावाट की ऑनसाइट सौर ऊर्जा क्षमता का विकास, संचालन और रखरखाव भी करेगा। साथ में, टीपीआरईएल की पवन और सौर स्थापनाएं हवाई अड्डे की टिकाऊ बिजली जरूरतों को पूरा करेंगी, जो टिकाऊ हवाई अड्डे के बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए टाटा पावर के समर्पण को रेखांकित करती है। हवाई अड्डे के परिचालन लचीलेपन को और मजबूत करते हुए, टाटा पावर ने आवश्यक विद्युत बुनियादी ढांचे सहित महत्वपूर्ण सूखी उपयोगिताओं का विकास किया है, और हवाई अड्डे की स्मार्ट ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 25 साल की अवधि में इस बुनियादी ढांचे के लिए संचालन और रखरखाव (ओ एंड एम) सेवाएं प्रदान करेगा। इसके लिए टाटा पावर और एनआईए के बीच पहले ही समझौते पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। यह अगले दो दशकों में 200 नए हवाई अड्डों के निर्माण सहित भारत के तेजी से बढ़ते हवाई अड्डे के बुनियादी ढांचे में हरित मॉडल को दोहराने की क्षमता को भी प्रदर्शित करता है। साझेदारी पर टिप्पणी करते हुए, टाटा पावर के सीईओ और एमडी, डॉ. प्रवीर सिन्हा ने कहा कि टाटा पावर को नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण में अग्रणी बनने के लिए नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के साथ साझेदारी करने पर गर्व है। जैसे-जैसे राष्ट्र अपने विमानन बुनियादी ढांचे को बढ़ा रहा है, हम नवीन स्वच्छ ऊर्जा समाधान प्रदान करके इस कार्य का नेतृत्व कर रहे हैं। यह सहयोग नेट जीरो हवाई अड्डों के विकास का समर्थन करेगा।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA
Corporate Communications Directorate

RS DAINIK JAGRAN DELHI 8 NOVEMBER 2024

नोएडा एयरपोर्ट की 50% बिजली की जरूरत सौर ऊर्जा व पवन ऊर्जा से होगी पूरी

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा : टाटा पावर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बिजली जरूरतों को पूरा करने के लिए 550 करोड़ का निवेश करेगी। एयरपोर्ट की पचास प्रतिशत बिजली जरूरत को पवन ऊर्जा व सौर ऊर्जा से पूरा किया जाएगा। नई दिल्ली में यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रा. लि. और टाटा पावर के बीच गुरुवार को अनुबंध किया गया। इसके तहत 10.8 मेगावाट बिजली पवन ऊर्जा से प्राप्त की जाएगी। सौर ऊर्जा के लिए एयरपोर्ट साइट पर 13 मेगावाट क्षमता का प्लांट लगाया जाएगा। इसे विकसित करने, संचालन एवं मेंटेनेंस की जिम्मेदारी टाटा पावर की सहयोगी कंपनी टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लि. की होगी। एयरपोर्ट परिसर के बिजली उपकरण व इंफ्रास्ट्रक्चर की देखरेख की जिम्मेदारी भी कंपनी की होगी। दोनों कंपनियों के बीच 25 वर्ष की अवधि के लिए अनुबंध किया गया है। टाटा पावर परियोजना में कुल 550 करोड़ रुपये का निवेश करेगी।

Tata Power to Invest ₹550 cr for RE Supply to Noida Airport

New Delhi: Tata Power will invest ₹550 crore to develop solar and wind power capacities and related infrastructure to supply clean energy to Noida International Airport (NIA), a statement said.

Tata Power has signed two power purchase agreements with the upcoming Noida International Airport project in Uttar Pradesh.

"Tata Power has entered into a strategic partnership for RE integration with Noida International Airport (NIA). Tata Power will invest ₹550 crore ($66 million) in solar and wind power supply, and the development of critical dry utilities and smart energy infrastructure," the company said in a statement. Under the arrangement, Tata Power's arm Tata Power Trading Company Ltd will supply 10.8 MW of wind power to the airport with secured assets from Tata Power Renewable Energy.

TPREL will also develop, operate, and maintain a 13 MW onsite solar power capacity to contribute to the airport's overall energy needs. Tata Power CEO and MD Praveer Sinha said, the move will help in "This collaboration will support development of Net Zero Airports, catering to millions of Indians, accelerating the country's path towards a greener future."

The first phase of airport, featuring one runway and one terminal, will have the capacity to handle traffic of 12 million passengers annually. -PTI

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

Corporate Communications Directorate

THE FINANCIAL EXPRESS DELHI 8 NOVEMBER 2024

Tata Power to invest ₹550 cr in solar & wind capacities at Noida airport

TATA POWER WILL invest ₹550 crore to develop solar and wind power capacities and related infrastructure to supply clean energy to Noida International Airport, a statement said.

"Tata Power has entered into a strategic partnership for RE integration with Noida International Airport (NIA). Tata Power will invest ₹550 crore ($66 million) in solar and wind power supply, and the development of critical dry utilities and smart energy infrastructure," the company said in a statement.

Under the arrangement, Tata Power's arm Tata Power Trading Company Ltd will supply 10.8 MW of wind power to the airport with secured assets from Tata Power Renewable Energy, which will also develop, operate, and maintain a 13 MW onsite solar power capacity to contribute to the airport's overall energy needs. —PTI

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA
Corporate Communications Directorate

HINDUSTAN | DELHI | 8 NOVEMBER 2024

एयरपोर्ट से गंगा एक्सप्रेसवे जुड़ेगा

तैयारी

लखनऊ/ग्रेटर नोएडा, विशेष संवाददाता। मेरठ से प्रयागराज तक बन रहा गंगा एक्सप्रेसवे अब नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर एयरपोर्ट से जुड़ेगा। इससे देश-विदेश से आने वाले यात्रियों को इस एक्सप्रेसवे के जरिए प्रयागराज तक सीधी कनेक्टिविटी मिल जाएगी।

इसके लिए गौतमबुद्ध नगर से मेरठ तक वाया बुलंदशहर नया लिंक एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। इस पर 4000 करोड़ रुपये खर्च होंगे। यह लिंक एक्सप्रेसवे 83 किलोमीटर लंबा होगा। यूपी सरकार के निर्देश पर यूपीडा ने हाल में सलाहकार कंपनी रेंडिकान इंडिया के जरिये इस प्रस्तावित एक्सप्रेसवे का सर्वे कराया था। उसने इस एक्सप्रेसवे की फिजीबिलिटी स्टडी व सर्वे रिपोर्ट यूपीडा को दी है। इसके मुताबिक गौतमबुद्धनगर व बुलंदशहर के 57 गांव चिन्हित किए गए हैं, जहां से यह एक्सप्रेसवे गुजरेगा। इसके लिए 1000 हेक्टेयर जमीन की जरूरत पड़ेगी। यह जमीन किसानों से खरीदी जाएगी या अधिग्रहीत होगी। जेवर एयरपोर्ट से जुड़ने से गंगा एक्सप्रेसवे की उपयोगिता और बढ़ जाएगी।

चारों लिंक एक्सप्रेसवे की प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल में चार नए लिंक एक्सप्रेसवे का ऐलान किया था। उन्होंने कहा कि जेवर में बन रहे विश्वस्तरीय एयरपोर्ट को एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाना चाहिए। इसके लिए, गंगा एक्सप्रेसवे से जेवर एयरपोर्ट तक लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण कराया जाए। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तक लिंक एक्सप्रेसवे भी बनाया जाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे से आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे तक वाया फर्रुखाबाद एक नया लिंक एक्सप्रेसवे बनाया जाना चाहिए। चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के साथ-साथ यह तीन नए एक्सप्रेसवे प्रदेश की तरक्की को तेज करने वाले होंगे। यूपीडा ने चारों एक्सप्रेसवे की प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार कर ली है।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA
Corporate Communications Directorate

JANSATTA DELHI 8 NOVEMBER 2024

नोएडा हवाई अड्डे पर पवन और सौर ऊर्जा से बनेगी बिजली

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 7 नवंबर।

550
करोड़ रुपए का समझौता किया टाटा पावर ने।

टाटा पावर नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को स्वच्छ ऊर्जा की आपूर्ति के लिए सौर और पवन ऊर्जा क्षमताओं और संबंधित बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 550 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। टाटा पावर ने उत्तर प्रदेश में बन रहे नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा परियोजना के साथ दो बिजली खरीद समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं।

कंपनी के मुताबिक, टाटा पावर ने नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा के साथ नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण के लिए रणनीतिक साझेदारी की है। टाटा पावर सौर और पवन ऊर्जा आपूर्ति तथा स्मार्ट ऊर्जा अवसंरचना के विकास में 550 करोड़ रुपए (6.6 करोड़ डालर) का निवेश करेगी। इस व्यवस्था के तहत, टाटा पावर की इकाई टाटा पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड (टीपीटीसीएल) टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड (टीपीआरईएल) की सुरक्षित परिसंपत्तियों के साथ हवाई अड्डे को 10.8 मेगावाट पवन ऊर्जा की आपूर्ति करेगी। टीपीआरईएल, हवाई अड्डे की समग्र ऊर्जा आवश्यकताओं में योगदान देने के लिए 13 मेगावाट की आनसाइट सौर ऊर्जा क्षमता का विकास, संचालन और रखरखाव भी करेगी।

Air India deploys additional resources at touch points, airports to help Vistara passengers

PTI ■ NEW DELHI

Air India has deployed additional resources, including help desk kiosks, at touch points and airports to ensure a smooth experience for Vistara passengers post its merger with the airline next week, an official said on Wednesday.

Full-service carriers - Air India and Vistara, a joint venture between Tatas and Singapore Airlines - set to be merged on November 11.

Post-merger, the routes and schedule operated by Vistara and the Vistara in-flight experience will remain the same.

Also, Vistara aircraft will be identified by a special four-digit Air India code beginning with the digit '2'.

The official in the know said Air India deployed additional resources across touch points in India, including help desk kiosks, at the curbside before terminal entry at hubs and metro city airports.

There will be "customer support staff wearing 'How may I assist you?' Air India x Vistara branded t-shirts for support", the official added.

In due course, Vistara airport ticketing offices and check-in terminals will become that of Air India.

Over the last few months, 2,70,000 customers who had booked Vistara flights have been migrated to Air India, and more than 4.5 million Vistara loyalty programme members are being migrated to Air India's loyalty programme.

There are concerns in certain quarters on whether Vistara passengers will continue to get the same services post-merger as Air India, which is in the transformation phase, has been facing certain service issues in recent times.

The Tata Group-owned Air India has emphasised that the Vistara experience will remain post-merger.

The integrated entity will have a fleet of more than 200 planes, offering connectivity to 90 domestic and international destinations.

RAJASTHAN PATRIKA DELHI 7 NOVEMBER 2024

रीवा एयरपोर्ट पांच नवंबर से शुरू होनी थी उड़ानें, डीजीसीए से जारी नहीं हो पाया शेड्यूल

उड़ानों की समय सीमा बीती, हवाई सफर की ख्वाहिश अधूरी

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

भोपाल. विंध्य के रीवा से 21 अक्टूबर 2024 को सबसे सस्ती हवाई सेवा शुरू करने का ऐलान हुआ था। एयरपोर्ट के लोकार्पण कार्यक्रम में 999 रुपए में हवाई सफर की बात कही गई थी। पांच नवंबर से नियमित फ्लाइट संचालित होनी थीं। यह तारीख निकल गई, लेकिन हवाई सेवा शुरू नहीं हो पाई। इस कारण विंध्य के लोग निराश हैं।

दरअसल, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (डीजीसीए) से अभी तक रीवा एयरपोर्ट से फ्लाइट संचालन को लेकर शेड्यूल जारी नहीं किया गया है। फ्लाइट कितने बजे उड़ेगी, दूसरा फेरा कब लगेगा, विमान की नाइट पार्किंग रीवा में होगी या भोपाल में। यहां बता दें कि फ्लाई बिग एयरलाइन का विमान लखनऊ से पहली उड़ान भरकर चित्रकूट, खजुराहो होते हुए रीवा एयरपोर्ट पहुंचेगा। जहां से भोपाल के लिए नियमित उड़ान भरेगा।

लोग ढूंढ़ते रह गए ऑनलाइन बुकिंग

दीपावली और छठ पर्व के कारण लोग रीवा जाने और वहां से फ्लाइट बुक करने ऑनलाइन साइट सर्च करते रह गए, लेकिन कहीं भी टिकट बुकिंग का सिस्टम नजर नहीं आया। इंदौर में नौकरी करने वाले आशीष दिवाली में घर गए थे। उन्होंने प्लेन से लौटने के लिए ट्रेन में टिकट नहीं करवाया था। सोचा था फ्लाइट का सफर कर लेंगे, लेकिन यात्रा का शेड्यूल ही बिगड़ गया। शेड्यूल के संबंध में कहीं से भी कोई उचित जानकारी नहीं मिली।

ऑपरेशन 15 से

फ्लाई बिग एयरलाइन के ग्राउंड ऑपरेशन हेड रतन लक्ष्मणराव ने पत्रिका से बातचीत में बताया कि कुछ दिक्कतें आ रही थीं, जिन्हें ठीक कर लिया गया है। नई-नई पॉलिसी की वजह से कुछ दिक्कतें होती हैं। अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि 15 नवंबर से ऑपरेशन शुरू कर देंगे। प्रस्ताव बनाकर डीजीसीए को भेज दिया गया है।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA
Corporate Communications Directorate

RAJASTHAN PATRIKA JAIPUR 7 NOVEMBER 2024

कोटा ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा : डीपीआर का कार्य पूरा

दिसंबर 2027 में उड़ान भरेंगे प्लेन

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

नई दिल्ली. कोटा में प्रस्तावित ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे के निर्माण कार्य को भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है। जरूरी स्वीकृतियां व औपचारिकताएं पूरी करने के बाद मई 2025 से हवाई अड्डे का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा। इस हवाई अड्डे से दिसंबर 2027 तक हवाई जहाजों की उड़ान शुरू किया जाएगा। पायलटों के प्रशिक्षण के लिए फ्लाइंग क्लब व फ्लाइंग स्कूल भी खोला जाएगा। संसद भवन में बुधवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक में परियोजना को लेकर कई निर्णय किए गए।

बिरला की अध्यक्षता में हुई बैठक में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआई) के चेयरमैन, अधिकारी व राजस्थान के सार्वजनिक निर्माण विभाग, वन विभाग समेत अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक हाइब्रिड मोड में आयोजित की गई। इसमें हवाई अड्डे के निर्माण की प्रगति, पर्यावरणीय पहलुओं, और अन्य आवश्यक स्वीकृतियों की समीक्षा की गई। राजस्थान के वन विभाग के हेड ऑफ फॉरेस्ट अरीजीत बनर्जी ने बताया कि हवाई अड्डे के निर्माण के लिए भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय से भूमि हस्तांतरण की अनुमति प्राप्त हो गई है। राजस्थान सरकार के वन विभाग ने भी इस परियोजना को स्वीकृति दे दी है। स्पीकर ओम बिरला की पहल पर पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से केडीए की ओर से 10 हजार नए पेड़ भी लगाए जाएंगे।

अंतिम चरण में डीपीआर

परियोजना की डीपीआर अंतिम चरण में है, जिसे इसी महीने पूरा किया जाएगा। परियोजना के पहले चरण में 1005 एकड़ क्षेत्रफल में 3200 मीटर लंबी हवाई पट्टी, 7 पार्किंग, 20000 वर्ग मीटर टर्मिनल बिल्डिंग, 14 चैक-इन काउंटर, 2 कन्वेयर बेल्ट के साथ सलाना 20 लाख यात्रियों के लिए परिवहन सुविधाएं विकसित की जाएंगी।

कोटा हवाई अड्डे से जुड़े फैक्ट

- 25 किमी. दूर कोटा शहर से
- 1005 एकड़ क्षेत्र में निर्मित होगा
- 3200 मीटर लंबा और 45 मीटर चौड़ा रनवे बनेगा
- 7 विमान पार्किंग का निर्माण होगा
- प्रति वर्ष 20 लाख यात्रियों और प्रति घंटे 1,000 यात्रियों की क्षमता प्रदान करेगा
- 4 लेन की 30 मीटर संपर्क सड़क बनेगी

RASHTRIYA SAHARA DELHI 8 NOVEMBER 2024

नोएडा हवाई अड्डे को स्वच्छ ऊर्जा की आपूर्ति करेगी टाटा पावर

टाटा पावर करेगी 550 करोड़ रुपए का निवेश

नई दिल्ली (एसएनबी)। टाटा पावर नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (एनआईए) को स्वच्छ ऊर्जा की आपूर्ति के लिए सौर और पवन ऊर्जा की आपूर्ति करेगी। क्षमताओं को बढ़ाने से लेकर बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कंपनी 550 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। कंपनी ने जारी बयान में यह जानकारी दी है।

टाटा पावर ने उत्तर प्रदेश में बन रही नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा परियोजना के साथ दो बिजली खरीद समझौते (पीपीए) पर हस्ताक्षर किए हैं। टाटा पावर की इकाई टाटा पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड (टीपीटीसीएल) टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड (टीपीआरईएल) के साथ हवाई अड्डे को 10.8 मेगावाट पवन ऊर्जा की आपूर्ति करेगी। साथ ही टीपीआरईएल हवाई अड्डे की समग्र ऊर्जा आवश्यकताओं में योगदान देने के लिए 13 मेगावाट की ऑन साइट सौर ऊर्जा क्षमता का विकास, संचालन और रख-रखाव भी शामिल है। टाटा पावर के सीईओ और प्रबंध निदेशक प्रवीण सिन्हा ने बताया कि यह सहयोग शुद्ध शून्य हवाई अड्डा के विकास में सहायता करेगा। लाखों भारतीयों की जरूरतों को पूरा करेगा और देश को हरित भविष्य की ओर ले जाएगा। नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण में एक हवाई पट्टी और एक टर्मिनल होगा, जिसकी क्षमता सालाना 1.2 करोड़ यात्रियों की आवाजाही को संभालने की होगी। पूरी तरह तैयार होने पर हवाई अड्डे की सालाना क्षमता सात करोड़ यात्रियों की होगी।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA
Corporate Communications Directorate
THE TIMES OF INDIA DELHI 8 NOVEMBER 2024

DIAL proposes to finish work at Terminal 1 by March 2025

Times News Network

New Delhi: Delhi International Airport Ltd (DIAL) on Thursday proposed to complete Terminal-1 interior restoration by Jan and the work on the external side by March. The GMR-backed airport operator made a presentation to the Union aviation ministry, which will decide the timeline of the restoration work.

The two options being weighed by govt are either to implement the plan that DIAL has got prepared from Larsen & Toubro at the earliest so that the work is over by next March or begin it after winter. A decision is expected shortly, say people in the know. "The L&T plan has been run by IIT Delhi. There was some thinking on allowing T1 to handle some more flights till the repair work is complete. But DIAL was not in favour of the same as a matter of abundant precaution. The aviation ministry is going to decide the future course of action very soon," said sources.

Govt had directed DIAL to get any plan for T1 approved by it before implementing the same.

Union aviation minister Ram Mohan Naidu is learnt to be weighing all options. While the expanded T1 was to handle 4 crore passengers annually, it is currently operating at a fraction of that capacity due to the collapse of a canopy and part of roof built in 2009-10 this June following heavy rainfall, killing a person. Govt had set up a high-level expert committee comprising IIT-Delhi's structural engineers to assess the roof collapse incident.

For airlines and passengers, this is the second "winter of discontent" at the country's busiest airport. Last winter, there was an issue with fog landings as only one runway had a CAT III instrument landing system. This time, there is a terminal-side capacity crunch since the collapse in June. T3 is massively overcrowded as it handles more flights along with the nearby T2 as the expanded T1 is yet to get fully operational. Once T1 gets operational as per capacity, the other terminals – T2 and T3 – will see a marked reduction in congestion.

THE TIMES OF INDIA CHENNAI 7 NOVEMBER 2024

Bomb hoax at Kovai airport

Coimbatore: The city airport received a hoax bomb threat email on Wednesday, forcing authorities to beef up security checks.

According to an official source, the airport received an email in the morning, stating a bomb was planted on its premises and would go off anytime. Airport authorities immediately alerted police and the bomb detection and disposal squad.

"They combed the entire premises and found that it was a bomb hoax. Nonetheless, security was strengthened as chief minister M K Stalin was scheduled to take a flight to Chennai from the airport," the source said.

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA
Corporate Communications Directorate

THE ASSAM TRIBUNE GUWAHATI 7 NOVEMBER 2024

Air India deploys addl resources at touch points

NEW DELHI/KOLKATA, Nov 6: Air India has deployed additional resources, including help desk kiosks, at touch points and airports to ensure a smooth experience for Vistara passengers post its merger with the airline next week, an official said on Wednesday. Full-service carriers – Air India and Vistara, a joint venture between Tatas and Singapore Airlines – are set to be merged on November 12. Post-merger, the routes and schedule operated by Vistara and the Vistara in-flight experience will remain the same. The official in the know said Air India deployed additional resources across touch points in India, including help desk kiosks, at the curbside before terminal entry at hubs and metro city airports. There will be "customer support staff wearing 'How may I assist you?' Air India x Vistara branded T-shirts for support", the official added. – PTI

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

Corporate Communications Directorate

AMAR UJALA DELHI 8 NOVEMBER 2024

जेट एयरवेज अब नहीं भरेगी उड़ान, शीर्ष कोर्ट ने संपत्तियां बेचने की दी अनुमति

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। ढाई दशक तक करोड़ों लोगों को हवाई सफर कराने वाली विमानन कंपनी जेट एयरवेज की उड़ान भरने की उम्मीदें अब पूरी तरह खत्म हो गईं। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 से बंद पड़ी विमानन कंपनी की दिवालिया कार्यवाही मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। शीर्ष कोर्ट ने बृहस्पतिवार को राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) की ओर से स्वीकृत समाधान योजना को खारिज करते हुए दो टूक कहा, अब कोई विकल्प नहीं बचा है। जेट एयरवेज का सफर खत्म। विमानन कंपनी की सभी संपत्तियां बेचनी ही होंगी।

शीर्ष कोर्ट ने जेट एयरवेज के परिसमापन, सफल बोलीदाता जालान कालरॉक कंसोर्टियम (जेकेसी) की ओर से डाले गए 200 करोड़ जब्त करने और एसबीआई के नेतृत्व वाले ऋणदाताओं को 150 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी भुनाने की अनुमति दे दी। जेट एयरवेज की आखिरी उड़ान एस2-3502 अमृतसर से 17 अप्रैल, 2019 को रात 10.30 बजे रवाना हुई और 18 अप्रैल को तड़के 12.22 बजे मुंबई के छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर उतरी थी।

असाधारण शक्तियों के इस्तेमाल पर एनसीएलएटी को फटकार

सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा ने संविधान के अनुच्छेद 142 के अंतर्गत मिली असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए एनसीएलएटी के आदेश को खारिज कर दिया और दिवालिया कार्यवाही पर रोक लगा दी। पीठ ने इस मामले को आंख खोलने वाला करार दिया।

साथ ही, जालान कालरॉक कंसोर्टियम (जेकेसी) के पहली किस्त के भुगतान के मद्देनजर प्रदर्शन बैंक गारंटी के समायोजन की अनुमति देने के लिए एनसीएलएटी की खिंचाई भी की। शीर्ष अदालत ने कहा, एनसीएलएटी ने जेकेसी को उसके भुगतान दायित्वों का पालन किए बिना ही जेट एयरवेज के अधिग्रहण की अनुमति दे दी थी।

आदेश की अवहेलना है गारंटी समायोजन निर्देश

पीठ ने कहा, एनसीएलएटी का सफल समाधान आवेदक को 350 करोड़ के भुगतान की पहली किस्त के विरुद्ध 150 करोड़ की बैंक गारंटी को समायोजित करने का निर्देश देना इस अदालत के पूर्व आदेश की अवहेलना है। एनसीएलएटी ने रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों को गुमराह किया। जस्टिस पारदीवाला ने एनसीएलएटी के फैसले के खिलाफ एसबीआई व अन्य ऋणदाताओं की याचिका को स्वीकार कर लिया, जिन्होंने एनसीएलएटी के निर्णय की वैधता को चुनौती दी थी।

■ कॉलरॉक कंसोर्टियम ने शर्तों का किया उल्लंघन

पीठ ने कहा, जेकेसी ने समाधान योजना की शर्तों का उल्लंघन किया है। इसे लागू नहीं किया जा सकता। मूल चिंता पर्याप्त न्याय करना नहीं, बल्कि विवाद का त्वरित निपटान है। हमें सुनिश्चित करना होगा कि कॉरपोरेट ऋणदाता के लिए परिसमापन एक विकल्प बना रहे। हम निर्देश देते हैं कि कॉरपोरेट देनदार को परिसमापन में ले जाया जाए। ऋणदाताओं को बैंक गारंटी को भुनाने की अनुमति है। एनसीएलटी मुंबई को तत्काल परिसमापक नियुक्त करना है।

अब 1.48 लाख खुदरा निवेशकों के डूबे पैसे

जेट एयरवेज में इस समय 1,48,128 खुदरा निवेश हैं। कंपनी बंद होने से अब इन्हें एक रुपये भी नहीं मिलेगा क्योंकि शेयर को रिस्क कैपिटल माना गया है। जेट का शेयर पिछले साल दिसंबर में 66 रुपये का था, जो अब 34 रुपये पर है।

कंपनी परिचालन बंद होने के बाद से 20,000 से अधिक नौकरियां जा चुकी हैं। ऋणदाताओं, विक्रेताओं व यात्रियों के हजारों करोड़ डूब गए हैं।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA
Corporate Communications Directorate

BUSINESS LINE DELHI 8 NOVEMBER 2024

Aircraft seat manufacturer Recaro to start India sourcing to support mega orders

Rohit Vaid
New Delhi

Mark Hiller(left), CEO of Recaro Aircraft Seating and RecaroECARO Holding, and IndiGo CEO Pieter Elbers PTI

Global aircraft seating manufacturer Recaro plans to commence sourcing from India in collaboration with local industry to support the mega orders that it has recently bagged from India-based airlines.

Speaking to *businessline*, Recaro's Chief Executive Mark Hiller said that the global aircraft seat manufacturer will start sourcing activities for "some materials" used for seat dressings from India. "We will be sourcing seat dress covers... We are also looking at other components that can be sourced from India," Hiller said.

"This will not only help Indian airlines source Recaro-certified or authorised dress covers locally, but also provide an opportunity for an Indian company to export them to Recaro at a competitive price." Accordingly, the project to source dressing materials from India is expected to be finalised by 2024-end.

INDIGO, AI ORDERS

Recently, the company's seats were selected by IndiGo for its premium product, IndiGo Stretch. Recaro will provide its R5 business class seats for narrow-body aircraft to IndiGo. These seats will be installed in 45 A321 Neo, while R2 will be fixed in economy class.

IndiGo has ordered a total of 45 shipsets to meet this upgrade, with each A321neo aircraft featuring 12 business class seats and 208 economy class seats. Besides, the seat manufacturer will provide the complete cabin layover in IndiGo A321 XLRs. The airline has ordered over 60 XLRs, which will be delivered from 2025.

Recaro has also bagged orders for more than 20,000 economy and 2,500 premium economy seats from Air India. "We have enough capacity at our sites in Germany, Poland and South Africa to fulfil the demand from airlines in India," Hiller said.

The price for the seats vary but on average, an economy class seat costs about €5,000 (approximately ₹4,52, 500) while a business class seat can be above €100,000 (₹90,50,000).

According to Hiller, seats on India's domestic aircraft are getting more premium as passengers look for high-quality, comfortable and premium seating.

"The first look in the aircraft cabin is at the seats and how beautifully they are dressed up. The selection of materials, colour design and stitching patterns makes a big impact on the seat look and comfort."

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA
Corporate Communications Directorate

BUSINESS STANDARD DELHI 8 NOVEMBER 2024

जेट एयरवेज के परिसमापन का आदेश

उच्चतम न्यायालय ने ठप पड़ी विमान कंपनी जेट एयरवेज के परिसमापन करने का आदेश दिया। परिसमापन की प्रक्रिया में कंपनी की संपत्तियों को बेचकर प्राप्त धन से ऋणों का भुगतान किया जाता है। इसके साथ ही जेट एयरवेज के लिए सफल बोलीदाता जालान कलरॉक गठजोड़ द्वारा डाले गए 200 करोड़ रुपये जब्त करने तथा भारतीय स्टेट बैंक की अगुआई वाले ऋणदाताओं को 150 करोड़ रुपये की प्रदर्शन बैंक गारंटी भुनाने की अनुमति दे दी।

संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा के पीठ ने राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील पंचाट (एनसीएलएटी) के आदेश को खारिज करते हुए जेट एयरवेज की दिवालिया कार्यवाही पर रोक लगा दी।

पीठ ने मामले को 'आंखें खोलने वाला' करार दिया और जालान कलरॉक गठजोड़ (जेकेसी) द्वारा पहली किस्त के भुगतान के मद्देनजर प्रदर्शन बैंक गारंटी का उपयोग करने की अनुमति देने के लिए एनसीएलएटी की खिंचाई की। एनसीएलएटी ने जेकेसी को अपने भुगतान दायित्वों का पूर्णतः पालन किए बिना ही जेट एयरवेज का अधिग्रहण करने की अनुमति दे दी थी।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA
Corporate Communications Directorate

BUSINESS STANDARD DELHI 8 NOVEMBER 2024

Jet flies into sunset as SC orders liquidation

Kalrock's bid funds forfeited; lenders permitted to encash bank guarantee

BHAVINI MISHRA
New Delhi, 7 November

The Supreme Court on Thursday ordered liquidating grounded Indian carrier Jet Airways, saying "it had no choice" but to do so.

The Bench of Chief Justice of India (CJI) D Y Chandrachud and judges J B Pardiwala and Manoj Misra said liquidation was the best option because the Jalan-Kalrock Consortium (JKC), the successful bidder for the airline, failed to implement the resolution plan even five years after its approval.

"We hold that the successful resolution applicant has contravened the terms of resolution plan and the corporate debtor is directed to be taken into liquidation. The fundamental concern is not to do substantial justice but also bring speedy disposal of dispute. The determination of the resolution plan has been contravened. Since it is not possible to implement the resolution plan, we have to ensure that liquidation remains an option for the corporate creditor," the judgment said.

Before pronouncing the order, Justice Pardiwala orally said: "This litigation is an eye-opener, and has taught us many lessons about the Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) and the functioning of National Company Law Appellate Tribunal (NCLAT)."

The court exercised its extraordinary powers under Article 142 to set aside an NCLAT decision to uphold a resolution plan and transfer ownership -- to the JKC -- without full payment to lenders.

The National Company Law Tribunal in Mumbai (NCLT) has been asked to appoint a liquidator immediately.

The court held ₹200 crore infused by the consortium stood forfeited and directed lenders to invoke a performance bank guarantee of ₹150 crore.

"We exercise plenary powers and direct that the corporate debtor (that is Jet Airways) is taken into liquidation. Appeals succeed. The NCLAT order (has been) set aside -- in peculiar and alarming circumstance since five years passed since the NCLAT cleared the resolution plan. Thus under Article 142, we direct the corporate debtor be taken into liquidation and ₹200 crore stands forfeited. Lenders are permitted to encash the performance bank guarantee. The NLCT Mumbai to appoint liquidator forthwith," the court said.

The NCLAT had on March 12 upheld the resolution plan of the grounded airline and approved the transfer of its ownership to the JKC. It had told the JKC to obtain an air operator's certificate within 90 days. It had also given it more time to pay ₹175 crore to State Bank of India (SBI) as 107 days had passed since the NCLAT's order allowing the transfer of ownership.

The lenders, led by SBI and comprising Punjab National Bank and JC Flowers Asset Reconstruction, challenged the NCLAT verdict.

During the hearing in the apex court, the JKC alleged SBI had given loans to previous companies without security and that was why they are foundering now.

SBI, meanwhile, said the bank guarantee of ₹150 crore should not be used even if expressly mentioned in the resolution plan.

"Respondents can adjust the performance bank guarantee upon execution of the mortgage of all the three Dubai properties, which the respondents have failed to do even today (Thursday)," Additional Solicitor General N Venkataraman said.

The NCLAT had directed the lenders of Jet Airways to adjust the ₹150 crore paid by the JKC as performance bank guarantee.

The bank said of the ₹350 crore payment, which is the first tranche, only ₹200 crore had been paid. It said its air operator certificate (expired in September 2023 and was never extended.

"Beyond the confines of the aviation industry, this judgment is expected to engender a climate of circumspection and diligence among future investors, particularly within asset-intensive sectors where revival efforts are fraught with regulatory and financial complexities," Tushar Kumar, advocate, Supreme Court of India, said.

THE STORY, BRIEFLY

2019
Apr: Jet Airways halts operations, burdened by debt and unpaid dues
Jun: Jet admitted for insolvency; NCLT begins seeking resolution plans

2020
Oct: Jalan-Kalrock Consortium (JKC) wins the bid to revive Jet Airways

2021
Jun: NCLT approves JKC's resolution plan

2023
Jan: NCLT allows JKC to take ownership of Jet Airways, lenders move NCLAT

2024
Mar: NCLAT confirmed transfer of ownership of airline to JKC, lenders move SC
Nov: SC orders liquidation of Jet Airways

BUSINESS STANDARD DELHI 8 NOVEMBER 2024

TCS bags multi-year deal from Air France-KLM

India's largest IT services company Tata Consultancy Services (TCS) bagged a multi-year deal to assist Air France-KLM in transitioning to an advanced, AI-ready, and cloud-native data landscape, according to a release. The deal would help Air France-KLM – a Europe-based global aviation leader in passenger transport, cargo transport and aeronautical maintenance – "become the most data-centric airline group in the world", the release added. PTI

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA
Corporate Communications Directorate

DAINIK BHASKAR DELHI 8 NOVEMBER 2024

कैसे जेट एयरवेज अर्श से फर्श पर आ गई...

2008 की मंदी, प्राइस वॉर ने रोकी जेट की तेज उड़ान

भास्कर न्यूज, नई दिल्ली | सुप्रीम कोर्ट ने जेट एयरवेज के लिक्विडेशन का आदेश दिया है। यानी कंपनी के रिवाइवल की उम्मीदें खत्म हो गई हैं। एक समय भारतीय आसमान में जेट एयरवेज का रुतबा था। लेकिन इसके मालिक नरेश गोयल ने कुछ ऐसे फैसले किए कि कंपनी की हालत बिगड़ती चली गई। वित्तीय अनियमितताओं के चलते गोयल को जेल भी जाना पड़ा। आइए जानते हैं जेट एयरवेज की कहानी...

25 हजार करोड़ कर्ज, यात्रियों के भी 3,500 करोड़ बकाया

मई, 2019 में दुबई के रास्ते में एक एमिरेट्स विमान को रुकने के लिए कहा गया, जब वह मुंबई में उड़ान भरने जा रहा था। इमीग्रेशन अधिकारियों ने नरेश गोयल और पत्नी अनीता को उतार लिया। गोयल वह शख्स थे, जिन्होंने दो दशक एविएशन इंडस्ट्री पर राज किया था। भारी कर्ज के चलते अप्रैल 2019 में जेट के विमान ग्राउंडेड हो गए। कंपनी पर 25,000 करोड़ का कर्ज है। यात्रियों का 3,500 करोड़ बाकी है।

गोयल ने कैशियर के तौर पर की थी करियर की शुरुआत

पंजाब के संगरूर से आने वाले गोयल ने दिल्ली में अपने चाचा की ट्रैवल एजेंसी में कैशियर के रूप में काम शुरू किया था। उन्हें हर महीने 300 रुपए मिलते थे। यह कारोबार और कमाई बढ़ी। 1967 से 1974 तक उन्होंने कई विदेशी एयरलाइंस के साथ एसोसिएशन के जरिये ट्रैवल बिजनेस की बारीकियां सीखी।

1974 में शुरू की ट्रैवल एजेंसी जेट एयर, तब उड़ा था मजाक

1974 में गोयल ने जेट एयर नाम की ट्रैवल एजेंसी शुरू की। तब ट्रैवल एजेंसी का नाम एविएशन कंपनी जैसा रखने पर लोग मजाक उड़ाया करते थे। गोयल का जवाब होता- वो दिन भी आएगा।

उदारीकरण के बाद 1993 में जेट एयरवेज की शुरुआत

1990 यानी आर्थिक उदारीकरण के दौर में सरकार ने निजी एयरलाइंस के लिए रास्ते खोले। मई 1993 में जेट एयरलाइंस ने कमर्शियल ऑपरेशन शुरू किया। उस समय कंपनी को गल्फ एयर और कुवैत एयरवेज का सपोर्ट मिला, जिनकी कंपनी में 40% हिस्सेदारी थी। 2005 में कंपनी 1,900 करोड़ रुपए का आईपीओ लाई, जो पूरी तरह सफल रहा।

जरूरत से ज्यादा दाम पर एयर सहारा का अधिग्रहण बड़ी चूक

2007 में गोयल ने 2,200 करोड़ रुपए में एयर सहारा खरीद ली। एक्सपर्ट्स के मुताबिक एयर सहारा के लिए उन्होंने जरूरत से ज्यादा कीमत चुकाई। यह बड़ी चूक रही। इस बीच कंपनी तेजी से इंटरनेशनल रूट्स पर विस्तार किया। लेकिन वैश्विक मंदी से खर्च ब... कमाई घटती गई।

इंडिगो से प्राइस वॉर में पिछड़ी, कंपनी पर बढ़ता गया कर्ज

आर्थिक चुनौतियों से जूझ रही जेट एयरवेज ने कर्ज लेना शुरू किया। इस बीच कंपनी इंडिगो के साथ फेयर प्राइस वॉर में बनी रही। 2018 आते-आते चीजें बदतर होती चली गईं। फेयर प्राइस वॉर में भी इंडिगो, जेट एयरवेज से आगे निकल गई। और कंपनी कर्ज से नहीं उबर पाई।

उड़ान... जेट एयरवेज ने भारत और दुनिया भर में 65 से अधिक जगहों के लिए उड़ान भरी। इनमें यूरोप, मिडिल-ईस्ट, साउथ-ईस्ट एशिया और उत्तरी अमेरिका के डेस्टिनेशंस शामिल रहे।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA
Corporate Communications Directorate

DESHBANDHU DELHI 8 NOVEMBER 2024

अक्टूबर में घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या में वृद्धि

नई दिल्ली। घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या अक्टूबर में 6.3 प्रतिशत बढ़कर 138.5 लाख हो गई, जो पिछले महीने 130.3 लाख थी। यह जानकारी गुरुवार को जारी हुई एक रिपोर्ट में दी गई। क्रेडिट रेटिंग आईसीआरए के मुताबिक, घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या अक्टूबर में सालाना आधार पर 9.6 प्रतिशत बढ़ी है। यह अक्टूबर 2019 के प्री-कोविड स्तर 122.8 लाख से 12.8 प्रतिशत ज्यादा है। चालू वित्त वर्ष के पहले छह महीनों में (अप्रैल-अक्टूबर) तक हवाई यात्री की संख्या 5.9 प्रतिशत बढ़कर 932 लाख रही है। वित्त वर्ष 2024-25 की पहली छमाही में भारतीय विमान कंपनियों में 162.6 लाख अंतरराष्ट्रीय यात्रियों ने सफर किया। इसमें सालाना आधार पर 16 प्रतिशत की वृद्धि की गई। रिपोर्ट में कहा गया कि भारतीय एविएशन इंडस्ट्री का आउटलुक स्थिर बना हुआ है, क्योंकि हवाई यात्रियों के ट्रैफिक में नरमी आने की उम्मीद है और लागत भी स्थिर रह सकती है।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA
Corporate Communications Directorate

THE DAILY GUARDIAN DELHI 7 NOVEMBER 2024

SpiceJet announces eight new flights

TDG NETWORK
NEW DELHI

SpiceJet is further expanding its domestic network with the launch of eight new flights starting November 15. In the statement released on Wednesday, the airline announced that these new routes will connect Jaipur with Varanasi, Amritsar and Ahmedabad, while also linking Ahmedabad with Pune. This expansion follows the recent launch of 32 new flights in October 2024, including two international flights connecting Delhi with Phuket.

Last month, SpiceJet also commenced UDAN flights linking Shivamogga in Karnataka with Chennai and Hyderabad, and introduced double daily flights between Chennai and Kochi, enhancing connectivity across key regional and metropolitan cities."We are excited to announce the launch of new flights from Jaipur to Varanasi, Amritsar, and Ahmedabad, as well as from Ahmedabad to Pune, providing our passengers with greater flexibility and convenience," SpiceJet Chief Business Officer Debojo Maharshi said.

"These new flights reflect our commitment to supporting passenger demand across tier-II cities and beyond. With our expanded winter schedule, including international and UDAN routes, we aim to provide our customers with greater convenience, affordability, and seamless travel experiences," Maharshi added.

SpiceJet will deploy its 78-seater Q400 aircraft in these sectors. Bookings for the new flights are now open and tickets are available at the website of the airline, SpiceJet's mobile app and through online travel portals and travel agents.

On Monday, the airline received a significant boost, with Acuite Ratings & Research Limited upgrading its long-term rating by four notches to 'B+' and its short-term rating to A4. The rating agency has also assigned a 'Stable' outlook to the airline.

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA
Corporate Communications Directorate

DAINIK JAGRAN DELHI 8 NOVEMBER 2024

जेट एयरवेज की संपत्तियों को बेचने का सुप्रीम आदेश

- एनसीएलएटी का आदेश खारिज, कंपनी की दिवालिया कार्यवाही बंद
- कहा-कंपनी का लिक्विडेशन लेनदारों, श्रमिकों व अन्य के हित में

नई दिल्ली, प्रेट्र: सुप्रीम कोर्ट ने बंद पड़ी जेट एयरवेज की संपत्तियों को बेचने का आदेश दिया है। साथ ही सफल बोलीदाता जालान कालराक कंसोर्टियम द्वारा कंपनी में डाले गए 200 करोड़ रुपये जब्त करने और एसबीआइ के नेतृत्व वाले ऋणदाताओं को 150 करोड़ रुपये की परफार्मेंस बैंक गारंटी भुनाने की अनुमति देने का आदेश दिया है।

संविधान के अनुच्छेद-142 के तहत अपनी असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पार्डीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) के आदेश को खारिज करते हुए कंपनी की दिवालिया कार्यवाही को हमेशा के लिए बंद कर दिया। पीठ की ओर से फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति पारदीवाला ने एनसीएलएटी के फैसले के खिलाफ एसबीआइ और अन्य ऋणदाताओं की याचिका को स्वीकार कर लिया। याचिका में

जालान कालराक कंसोर्टियम के पक्ष में जेट एयरवेज की समाधान योजना को बरकरार रखने के फैसले का विरोध किया गया है। न्यायालय ने कहा कि विमानन कंपनी का परिसमापन (लिक्विडेशन) लेनदारों, श्रमिकों और अन्य हितधारकों के हित में है। परिसमापन की प्रक्रिया में कंपनी की संपत्तियों को बेचकर प्राप्त धन से ऋणों का भुगतान किया जाता है। पीठ ने एनसीएलएटी को, उसके फैसले के लिए फटकार भी लगाई। पीठ ने कहा, 'समाधान योजना को एनसीएलटी (राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण) द्वारा विधिवत स्वीकृत करने के बाद से लगभग पांच वर्ष बीत चुके हैं और कोई प्रगति नहीं हुई है। ऐसे में हमारे पास संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने और कारपोरेट देनदार को लिक्विडेशन के लिए निर्देश देने के अलावा और विकल्प नहीं बचा है।

एनसीएलएटी ने स्थापित कानूनी सिद्धांतों के खिलाफ काम किया : पार्डीवाला ने कहा, 'यह मामला एनसीएलएटी की कार्यप्रणाली सहित कई मुद्दों पर आंखें खोलने वाला रहा है।' उन्होंने कहा कि समाधान योजना को लागू करने में जालान कालराक कंसोर्टियम की विफलता ने दिवालिया प्रक्रिया के मामलों को प्रभावित किया है, जिसके लिए लिक्विडेशन जरूरी है। समाधान योजनाओं का समय पर अनुपालन दिवालिया कानून के उद्देश्य के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा, "हमारे मन में इस बात को लेकर कोई संदेह नहीं है कि एनसीएलएटी ने स्थापित कानूनी सिद्धांतों के विपरीत काम किया और गलत निष्कर्ष निकालने की हद तक चला गया"।

जेट एयरवेज ● फाइल फोटो

'कोलकाता दुष्कर्म मामले की सुनवाई बंगाल से बाहर नहीं'

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता में महिला डाक्टर के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या के मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए मुकदमे को बंगाल से बाहर स्थानांतरित करने से इन्कार कर दिया। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि निचली अदालत के न्यायाधीश के पास सुबूतों पर गौर करने के बाद जरूरी महसूस होने पर एक और जांच का आदेश देने के लिए पर्याप्त शक्तियां हैं। इस मामले में निचली अदालत में प्रतिदिन सुनवाई 11 नवंबर से शुरू होगी।

'जेलों में एनसीआरबी आंकड़ों के संग्रह में कोई अड़चन नहीं'

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जेलों में विचाराधीन कैदियों या दोषियों के रजिस्टर में जाति के किसी भी तरह के उल्लेख के साथ ही 'जाति' की प्रविष्टि हटाने संबंधी निर्देश से राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा आंकड़ों के संग्रह में कोई बाधा नहीं आएगी। सीजेआइ चंद्रचूड़ व दो जजों की पीठ ने गुरुवार को यह स्पष्टीकरण दिया। कोर्ट ने तीन अक्टूबर को दिए निर्णय में जेलों में जाति आधारित भेदभाव को प्रतिबंधित किया था और 10 राज्यों की जेल नियमावली को 'असंवैधानिक' करार दिया था।

...जब नकदी की कमी से जूझ रही कंपनी ने एक शाम परिचालन बंद करने का एलान किया

नई दिल्ली, प्रेट्र : पांच साल से भी अधिक समय पहले अप्रैल की एक शाम नकदी की कमी से जूझ रही जेट एयरवेज ने अस्थायी रूप से परिचालन बंद करने का एलान किया था। उस समय कंपनी में लगभग 20 हजार कर्मचारी थे और यात्रियों के रिफंड के हजारों करोड़ रुपये के अलावा बैंकों का 8,500 करोड़ रुपये से अधिक बकाया था। एक ट्रेवल एजेंट के तौर पर विमानन उद्योग से जुड़ने वाले नरेश गोयल ने इसकी स्थापना की थी। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा विमानन कंपनी के लिक्विडेशन का आदेश देने के बाद कंपनी के पुनरोद्धार को लेकर सभी उम्मीदें खत्म हो गईं। बढ़ते कर्ज से जब परिचालन बंद का एलान किया गया तो एयरलाइन के पास 16 विमान थे।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

Corporate Communications Directorate

DAINIK NAVJYOTI | JAIPUR | 7 NOVEMBER 2024

एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट्स रद्द, यात्री परेशान

नवज्योति, जयपुर। एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट्स के बार-बार रद्द होने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बुधवार को दिल्ली और कोलकाता की फ्लाइट्स के रद्द होने से यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा। दिल्ली से जयपुर आने वाली फ्लाइट सुबह 11.50 बजे पहुंचती है और जयपुर से दोपहर 12.20 बजे दिल्ली के लिए रवाना होती है। एयरलाइन कंपनी ने संचालन कारण बताते हुए इसे रद्द कर दिया। इसी तरह जयपुर से सुबह 8.55 बजे कोलकाता जाने वाली फ्लाइट का भी संचालन कारण बताते हुए रद्द किया।

वीजा में कमी से रूस जा रहे यात्री को शारजाह से लौटाया: जयपुर एयरपोर्ट पर एक यात्री को वीजा में कमी के चलते रूस जाने से रोक दिया गया। यह यात्री एयर अरबिया की फ्लाइट से मंगलवार

को शारजाह पहुंचा था और वहां से उसे रूस के लिए रवाना होना था। हालांकि वीजा में कमी पाए जाने पर उसे शारजाह में ही रोक दिया गया और आज सुबह उसे वापस जयपुर लौटा दिया गया। जयपुर एयरपोर्ट पर इमीग्रेशन अधिकारियों ने यात्री को फिर से रोककर वीजा में खामी की वजह से आगे की यात्रा को अनुमति नहीं दी।

फ्लाइट देरी से संचालित

एयर इंडिया एक्सप्रेस की जयपुर दोपहर 12.10 बजे हैदराबाद जाने वाली फ्लाइट शाम 5.05 बजे और जयपुर से दोपहर 2.15 बजे गुवाहाटी जाने वाली फ्लाइट शाम 4.40 बजे रवाना हुई।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA
Corporate Communications Directorate

THE ECONOMIC TIMES DELHI 8 NOVEMBER 2024

Jet, Set, No: SC Orders Liquidation

The Descent

- **MAY 1993** Jet Airways starts
- **DEC 2004** Lists on BSE
- **APRIL 2013** Etihad buys 24% in Jet
- **MAY 2018** Jet says net worth negative
- **FEB 2019** Debt converted into equity to close funding gap of ₹8,500 crore
- **March 2019** Founder NARESH GOYAL steps down as chairman, ousted from board with wife
- **April 2019** Airline suspends ops after banks refuse emergency ₹1,000 crore
- **Oct 2020** Jalan-Kalrock selected new owner
- **Oct 2023** SBI-led consortium moves SC for liquidation for non-payment
- **Nov 2024** SC orders liquidation

TEXT: Arindam Majumder

Indu Bhan

New Delhi: Jet Airways won't be returning to the skies.

The Supreme Court has ordered liquidation of the grounded carrier, after a consortium of UK-based Kalrock Capital and the UAE-based entrepreneur, Murari Lal Jalan, failed to implement its resolution plan.

The Naresh Goyal-founded airline, which was once considered India's best, had stopped flying in April 2019 after it ran out of money and couldn't service its debt.

Putting an end to the five-year-long insolvency process, the Supreme Court on Thursday said liquidation must be available to lenders as a last resort since the resolution plan can no longer be implemented.

The apex court rejected the takeover bid.

Lenders Can Invoke Performance Bank Guarantee ▸▸ 17

Performance Bank Guarantee

▸▸ **From Page 1**

The court said the ₹200 crore given by the Jalan-Kalrock (JKC) consortium, as part of the initial tranche payment of ₹350 crore, would have to be forfeited. Lenders can also invoke the performance bank guarantee of ₹150 crore, it said.

The court set aside the March order of the National Company Law Appellate Tribunal (NCLAT) that directed transfer of ownership of the debt-ridden airline to JKC.

A bench led by chief justice DY Chandrachud said the successful resolution applicant (JKC) had contravened the terms of the resolution plan and failed to infuse even the first tranche within the time stipulated. On Thursday, the top court said the appellate tribunal had acted against "settled legal principles."

"The resolution plan is incapable of being implemented. Therefore, we must make sure the avenue of liquidation stays alive," it said.

Under the "peculiar and alarming circumstances," and keeping in mind that "almost five years have elapsed since the resolution plan was duly approved by the NCLAT and there being no progress worth the name, we are left with no other option but to invoke our jurisdiction under Article 142 of the Constitution, and direct that the corporate debtor be taken in liquidation… while being mindful of the underlying objective—that time and speed are of the essence under the (Insolvency and Bankruptcy) Code."

NO PAYMENTS

The lenders led by State Bank of India (SBI) had challenged the NCLAT order, saying the consortium failed to implement its resolution plan, which had been approved by NCLT on June 22, 2021. The lenders said their total admitted claim was of ₹7,800 crore, but JKC had offered ₹4,783 crore, which was payable in parts over five years. "The first tranche payment of ₹350 crore was required to be made by March 21, 2022 (which has not been paid till date, despite several extensions given by NCLT/NCLAT/Supreme Court)," the lenders said in their appeal filed through counsel Sanjay Kapur.

According to the resolution plan, airport dues and parking charges of ₹475 crore, which have ballooned to ₹1,000 crore, were required to be paid upfront by JKC in 180 days. However, the March order had confined this liability to ₹25 crore toward airport dues, SBI said. JKC had denied the allegations, arguing it had spent ₹700 crore so far in trying to revive the airline, despite lenders objecting to every step it took and every move it made.

The committee of creditors approved a resolution plan submitted by JKC in 2020, to revive and operate the airline. Subsequently, a monitoring committee comprising lenders, the consortium and the resolution professional had been formed to oversee operationalisation of the airline.

BEST SERVING INTERESTS

The court on Thursday said the fundamental concern was not just to ensure "substantial justice," but also speedy disposal. "Since the resolution plan is no longer capable of being implemented, we must ensure that at least, liquidation remains as a viable last resort for the corporate debtor and its creditors," said the bench, which also comprised justices JB Pardiwala and Manoj Misra.

It directed the Mumbai bench of the National Company Law Tribunal (NCLT) to take appropriate steps for the appointment of a liquidator and other formalities.

Pardiwala, writing for the bench, said liquidation was the only viable option through which creditors could recover some of their dues. It would best serve interests, including of employees who are yet to receive their dues. The court said the case served as an "eye-opener" and has "taught us many lessons" about the functioning of insolvency tribunals and IBC.

In its 169-page judgement, the court said the appellate tribunal allowing JKC to adjust the performance bank guarantee of ₹150 crore toward its ₹350-crore first tranche payment was "perverse" and in "flagrant disregard" of its January 18 order.

The Supreme Court had, at the time, ordered JKC to deposit ₹150 crore in an escrow account jointly held by SBI and JKC.

The apex court also said the performance bank guarantee was to be kept alive till the completion of the resolution plan, as it could only be forfeited in breach of the plan.

The contention of JKC that adjustment of payment was permissible under the resolution plan must be rejected, the court said, adding that it had also breached clause 6.2 of the resolution plan, which required payment of the minimum dues of workmen. Jet Airways, which was established in 1992, was the country's second-biggest carrier at its height. Goyal is in jail, accused by ED of money laundering and diversion of money loaned to Jet Airways. ED arrested him on September 1, 2023.

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

Corporate Communications Directorate

THE ECONOMIC TIMES DELHI 8 NOVEMBER 2024

TCS Signs Pact with Air France-KLM

NEW DELHI: India's largest IT services company Tata Consultancy Services (TCS) has bagged a multi-year deal to assist Air France-KLM in transitioning to an advanced, AI-ready, and cloud-native data landscape, according to a release. The deal will help Air France-KLM—a Europe-based global aviation leader in passenger transport, cargo transport and aeronautical maintenance—"become the most data-centric airline group in the world," the release added. It will facilitate Air France-KLM's transition to an advanced, AI-ready, and cloud-native data landscape.

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA
Corporate Communications Directorate

THE FINANCIAL EXPRESS DELHI 8 NOVEMBER 2024

SC orders liquidation of Jet Airways

SWARAJ BAGGONKAR
Mumbai, November 7

THE SUPREME COURT on Thursday ordered the liquidation of Jet Airways, a little over five years after insolvency proceedings started against the carrier following its grounding in mid-2019.

The bench, comprising Chief Justice DY Chandrachud, Justice JB Pardiwala and Justice Manoj Misra, set aside an order of the National Company Law Appellate Tribunal (NCLAT). The appellate tribunal had allowed the transfer of ownership of the airline to Jalan Kalrock Consortium (JKC), which had emerged as the successful resolution applicant (SRA).

Continued on Page 11

SC orders liquidation of Jet Airways

THE SC RULED that the resolution plan was violated after JKC failed to infuse funds within the stipulated time frame. State Bank of India, the lead lender to the airline, and other creditors had contested the NCLAT's approval of the plan. JKC, according to the resolution plan, was to pay ₹4,783 crore with ₹350 crore as the first tranche of the payment.

The court observed that the liquidation of Jet Airways was in the best interest of the creditors, employees and other stakeholders. The SC asked the NCLT, Mumbai, to forthwith appoint the liquidator to carry out the liquidation. When contacted, JKC did not respond at the time of going to press. "This litigation is an eye-opener and has taught us many lessons about the IBC (Insolvency and Bankruptcy code), and the functioning of NCLAT," Justice Pardiwala said.

The Court observed that the liquidation of Jet Airways was in the best interest of the creditors, employees and other stakeholders

The order came just as another airline, Go First, failed to become operational again after having entered insolvency proceedings under the IBC. Go First lenders are also keen on liquidation.

Just three years before being completely grounded, Jet Airways was at an enviable position in the Indian aviation market. With a share of 21% (together with Jet Lite), the Naresh Goyal-led airline was the second-biggest and ahead of government-controlled Air India in the domestic market.

However, Jet had a bigger control on the international route. With its wide body planes, comprising Boeing 777s serving ultra-long-haul routes such as India-US and also the ever-busy India-Gulf routes, it controlled 42% of the international traffic to and from India.

With plush and modern interiors of its new planes, especially the business class accompanied by notable service by its in-flight crew, Jet Airways became the preferred choice for international flyers.

Starting operations in 1993 as an air taxis operator, it was not until 1995 that Jet Airways received its scheduled airline status. Just before starting with the international operations in 2004, the company hit a peak market share of 44% in the domestic circuit. A year later it went public. In 2007, Jet acquired Air Sahara founded by Subrato Roy and later renamed it Jet Lite. The acquisition price of nearly ₹1,500 crore weighed heavily on Jet's operations. Its net worth turned negative in 2012 before debt ballooned to ₹8,500 crore in 2018.

FREE PRESS JOURNAL MUMBAI 7 NOVEMBER 2024

Vistara merger: Air India deploys addl resources at touch points, airports to help passengers

PTI
NEW DELHI/KOLKATA

Air India has deployed additional resources, including help desk kiosks, at touch points and airports to ensure a smooth experience for Vistara passengers post its merger with the airline next week, an official said on Wednesday.

Full-service carriers -- Air India and Vistara, a joint venture between Tatas and Singapore Airlines – are set to be merged on November 12. Post-merger, the routes and schedule operated by Vistara and the Vistara in-flight experience will remain the same. Also, Vistara aircraft will be identified by a special four-digit Air India code beginning with the digit '2'.

The official in the know said Air India deployed additional resources across touch points in India, including help desk kiosks, at the curbside before terminal entry at hubs and metro city airports.

There will be "customer support staff wearing 'How may I assist you?' Air India x Vistara branded t-shirts for support", the official added.

Besides, the staff will work with airport security to guide customers with old Vistara tickets to the nearest help desk or to Air India customer support staff and deploy advisory on self-service kiosks.

In due course, Vistara airport ticketing offices and check-in terminals will become that of Air India.

In the first month after the merger, nearly 1,15,000 passengers who had purchased Vistara tickets pre-merger are expected to fly on unified Air India, the official said.

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA
Corporate Communications Directorate

HINDUSTAN DELHI 8 NOVEMBER 2024

जेट एयरवेज के फिर उड़ान भरने की संभावना खत्म

फैसला

प्रभात कुमार

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में बंद पड़ी जेट एयरवेज की परिसंपत्तियों को बेचने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया। इस फैसले से दिवालिया हो चुकी जेट एयरवेज के लेनदारों, कर्मचारियों और अन्य हितधारकों को लाभ होगा क्योंकि संपत्तियों को बेचने के बाद पैसे का वितरण सभी लेनदारों और कर्मचारियों के बकाया भुगतान के लिए होगा।

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने एनसीएलएटी के 12 मार्च 2024 के फैसले को रद्द कर दिया। पीठ ने जेट की परिसंपत्तियों को बेचने की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल किया। इससे पहले एनसीएलएटी ने जेट एयरवेज की समाधान योजना को बरकरार रखने और इसका मालिकाना हक जालान कलरॉक कंसोर्टियम (जेकेसी) को हस्तांतरित किए जाने को मंजूरी दी थी।

पांच साल में लागू नहीं हुई समाधान योजना : सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि चिंताजनक परिस्थिति यह है कि समाधान योजना को पांच साल से लागू नहीं किया गया। पीठ ने एनसीएलटी मुंबई पीठ को तत्काल कंपनी की परिसंपत्तियों को बेचने के लिए लिक्विडेटर नियुक्त करने और लिक्विडेशन की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया।

200 करोड़ जब्त होंगे : पीठ ने जालान कलरॉक कंसोर्टियम द्वारा पहले जमा कराए गए 200 करोड़ रुपये की राशि जब्त करने कहा है। पीठ ने कहा है कि लेनदार 150 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी को भुनाने के हकदार हैं।

अर्श से फर्श पर कंपनी

- जेट एयरवेज ने 1993 में अपनी पहली उड़ान शुरू की थी। कंपनी पहली बार 2005 में शेयर बाजार में सूचीबद्ध हुई थी।
- अपने चरम पर कंपनी देश-विदेश के 74 शहरों के लिए रोजाना 300 उड़ानें संचालित करती थी।
- कंपनी के पास 120 से ज्यादा विमान, लगभग 1,300 पायलट समेत 20 हजार कर्मचारी थे।
- देश की सबसे बड़ी निजी एयरलाइंस में इसका नाम शुमार था। देश के हवाई यातायात में इसकी 21.2% हिस्सेदारी थी।
- 2017 के बाद से कंपनी की कमाई घटी और कर्ज का बोझ बढ़ा। साल 2019 में कंपनी ने खुद को दिवालिया घोषित करते हुए परिचालन को अस्थायी रूप से बंद किया।
- एयरलाइन की आखिरी उड़ान 17 अप्रैल 2019 को अमृतसर से मुंबई के बीच संचालित हुई थी।
- परिचालन ठप होने से बाद से करीब 20,000 से अधिक कर्मियों की नौकरियां जा चुकी हैं।

क्या है मामला : आर्थिक संकट की वजह से जेट एयरवेज का परिचालन वर्ष 2019 से बंद है। उस वक्त कंपनी पर 8500 करोड़ का कर्ज था। सबसे ज्यादा कर्ज एसबीआई ने दिया था। एयरलाइन के घाटे में जाने के बाद बैंकों ने दिवालिया की कार्रवाई शुरू की थी। एनसीएलटी ने मार्च में समाधान योजना के तहत जेट एयरवेज का मालिकाना हक जेकेसी को देने का फैसला सुनाया था। इसके खिलाफ बैंकों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी।

SC sets aside NCLAT ruling, orders Jet Airways liquidation

Jet Airways has been grounded since April 2019 because of a liquidity crisis

Utkarsh Anand
letters@hindustantimes.com

NEW DELHI: The Supreme Court on Thursday ordered the liquidation of Jet Airways while setting aside a National Company Law Appellate Tribunal (NCLAT) ruling in March that upheld the transfer of the defunct airline's ownership to the Jalan-Kalrock Consortium (JKC) under an approved resolution plan.

A bench led by Chief Justice of India (CJI) Dhananjaya Y Chandrachud, comprising justices JB Pardiwala and Manoj Misra, upheld the plea by State Bank of India (SBI) and other creditors challenging the NCLAT order, adding the court had to exercise its power under Article 142 to order liquidation of the debt-ridden air carrier because of the five-year delay in the completion of the resolution process.

"In the peculiar and alarming circumstances as discussed in this judgment and also keeping in mind the fact that almost five years have elapsed since the Resolution Plan was duly approved by NCLAT and there being no progress worth the name, we are left with no other option but to invoke our jurisdiction under Article 142 of the Constitution and direct that the corporate debtor be taken in liquidation," stated the bench, directing the National Company Law Tribunal (NCLT) to act accordingly.

The Supreme Court judgment brings to an end the protracted legal battle over the revival and ownership of air carrier. MINT

According to the bench, a determination that the terms of the resolution plan have been contravened by the successful resolution applicant (JKC) and since the resolution plan is no longer capable of being implemented, the court must ensure that at least liquidation remains as a "viable" last resort for the corporate debtor and its creditors.

Jet Airways has been grounded since April 2019 due to a liquidity crisis. In 2021, JKC won the bid to revive the airline, and Jet Airways indicated at the time that it could potentially be relaunched in 2024. The Supreme Court judgment brings to an end the protracted legal battle over the revival and ownership of air carrier, which has an admitted claim of the financial creditors to the tune of ₹7,800 crore.

The decision followed extensive deliberations on whether JKC fulfilled its obligations and whether creditors acted within their rights by seeking liquidation. The NCLAT ruling from March upheld the resolution plan for Jet Airways, authorising JKC's takeover and setting a 90-day deadline for completing the transfer of ownership. It also directed the adjustment of a ₹150 crore performance bank guarantee (PBG) paid by JKC.

This adjustment, the top court ruled on Thursday, was "perverse" and in contravention of a previous order of the court in January this year, the terms of the resolution plan and settled principles of law.

The creditors, represented by SBI, Punjab National Bank (PNB), and JC Flowers Asset Reconstruction Private Limited, appealed to the Supreme Court, challenging NCLAT's March decision. They argued that JKC had not fulfilled key obligations, including the infusion of ₹350 crore within the required time frame and meeting other financial commitments, such as mortgaging properties in Dubai. ASG N Venkatraman, appearing for the SBI-led consortium, cited reports suggesting that public lenders were bearing undue blame for delays in the revival process, pointing out that insolvency issues extended beyond creditor control.

Accepting the ASG's submissions, the bench on Thursday held that JKC failed to fulfil its obligations and contravened the terms of the resolution plan by meeting the financial commitments. "NCLAT fell in error in allowing the adjustment of PBG of ₹150 crore as a part of the first tranche payment. This is evident from the order of this court dated January 18 wherein it was held that an infusion of ₹350Crore would only mean an infusion by cash and the same could not be substituted for the adjustment of PBG...the impugned order passed by NCLAT is perverse and unsustainable in law," held the bench.

JKC, during the earlier proceedings, had argued that procedural delays, including security clearances, had obstructed JKC's efforts. It contended that JKC had incurred significant losses, over ₹600 crore, due to these delays and affirmed that the consortium had fulfilled its financial commitments, including an additional ₹100 crore infusion as recently as September 2023. But the bench rejected JKC's submissions. "The SRA herein has failed to infuse the first tranche payment of ₹350 crore as envisaged in the resolution plan despite the Effective date being fixed on May 20, 2022. As a consequence, the payment of CIRP costs, workmen and employees' dues etc. which must be made in priority over the dues of the other creditors have also not been made. More than 5 years have passed and the implementation of the Resolution Plan still seems to be a dim light at the far end of a long tunnel," it noted.

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA
Corporate Communications Directorate

THE HINDU CHENNAI 7 NOVEMBER 2024

Royal Brunei Airlines launches direct flight service to Chennai

Murali N. Krishnaswamy
CHENNAI

The Royal Brunei Airlines has begun direct flights on the Brunei-Chennai-Brunei sector, the airline announced here.

Chennai will be the carrier's sole destination in India. The airline flew to London via Kolkata and Dubai in the 1990s, but the service was suspended after the 9/11 attacks in the United States. It has operated some charter flights since then to stations such as Coimbatore.

Speaking to the media, Captain Sabirin Bin Hj Abdul Hamid, CEO of Royal Brunei Airlines, said, "India is one of the biggest markets for aviation and it is an ideal time to step in and we decided to choose Chennai to start flights here."

The inaugural Brunei-Chennai Royal Brunei flight at the Chennai International Airport on Tuesday. SPECIAL ARRANGEMENT

The aircraft on the inaugural flight from Brunei capital Bandar Seri Begawan had a special 'Brunei Tourism' livery, which highlights some of Brunei's landmarks, natural splendours, and a traditional songket pattern. A large delegation from the Brunei Economic Development Board was among the passengers who arrived on Tuesday night.

An airline official said the flight, BI121/BI122, a three-days-a-week service (Tuesday, Thursday, Saturday), is to be operated with a 150-seat two-class configured Airbus A320N, and would boost business and tourism between the sultanate on the island of Borneo and southern India.

Officials from the STIC Travel Group, the airline's India GSA, said Brunei has an Indian diaspora largely from Tamil Nadu and Kerala, and the flag carrier was looking to tap into business, labour, tourism, student, and professional traffic. Another travel segment was onward traffic to other southeast Asian destinations and also Melbourne, Australia. The airline has an interline agreement with Air India to connect passengers from Bengaluru, Coimbatore, Hyderabad, Mumbai, and New Delhi to the Chennai flight.

THE INDIAN EXPRESS DELHI 8 NOVEMBER 2024

TCS bags multi-year deal from Air France-KLM

New Delhi: India's largest IT services company Tata Consultancy Services (TCS) has bagged a multi-year deal to assist Air France-KLM in transitioning to an advanced, AI-ready, and cloud-native data landscape, according to a release. The deal will help Air France-KLM - a Europe-based global aviation leader in passenger transport, cargo transport and aeronautical maintenance - "become the most data-centric airline group in the world", the release added. It will facilitate Air France-KLM's transition to an advanced, AI-ready, and cloud-native data landscape. **PTI**

JANSATTA DELHI 8 NOVEMBER 2024

उड़ानों के दौरान भी अब कर सकेंगे इंटरनेट का इस्तेमाल

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 7 नवंबर।

जल्द ही यात्रियों को उड़ानों में सफर के दौरान इंटरनेट के इस्तेमाल का मौका मिलेगा। देश की तमाम एअरलाइन में यात्रियों को सुविधाएं शुरू होने का इंतजार है।

भारत सरकार ने हाल ही उड़ान में वाई फाई के इस्तेमाल की अनुमति दे दी है। इससे रोजाना विमानों में सफर करने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। हालांकि, इस सुविधा का उपयोग सिर्फ उस वक्त किया जा सकेगा, जब विमान में इलेक्ट्रानिक उपकरणों के उपयोग करने की इजाजत होगी और उड़ान, भारतीय हवाई क्षेत्र में 3,000 मीटर की ऊंचाई पर हो। इससे विमान यात्रियों को सफर में भी वाट्सएप और यूट्यूब के इस्तेमाल का मौका मिल सकेगा।

उड़ान और समुद्री संपर्क नियम, 2018 के तहत सरकार ने अनिवार्य कर दिया है कि उड़ान और समुद्री संपर्क सेवा प्रदाता स्थलीय मोबाइल नेटवर्क के साथ हस्तक्षेप से बचने के लिए भारतीय हवाई क्षेत्र में न्यूनतम 3,000 मीटर की ऊंचाई पर विमान में मोबाइल संचार सेवाओं के संचालन की अनुमति प्रदान करेंगे। अधिसूचित नए नियम के अनुसार, 'उप-नियम (1) में उल्लिखित भारतीय हवाई क्षेत्र में न्यूनतम ऊंचाई के बावजूद, विमान में वाई-फाई के माध्यम से इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

Corporate Communications Directorate

LOKSATYA DELHI 8 NOVEMBER 2024

घरेलू हवाई किराए में बीते पांच साल में हुई 43 फीसदी की बढ़ोतरी

वियतनाम के बाद दुनिया में ऐसा करने वाला दूसरा देश बना भारत

मुंबई, एजेंसी। घरेलू हवाई किराया भारत में काफी बढ़ गया है। एशिया-प्रशांत (एपीएसी) और पश्चिम एशियाई क्षेत्रों में घरेलू हवाई किराया बढ़ा है। ये हवाई किराए की दूसरी सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। इसमें वर्ष 2019 की महामारी के पूर्व स्तर की तुलना में वर्ष 2024 की पिछली छमाही में कीमत में 43 फीसदी का इजाफा देखा गया है। वियतनाम के बाद इतनी बढ़ोतरी करने वाला भारत दूसरा देश है। वियतनाम में हवाई किराए में 63 फीसदी का इजाफा देखने को मिला है। इस संबंध में बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट की मानें तो इस समयसीमा के दौरान अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा के किराए में बढ़ोतरी करने के मामले में भारत के बाद संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और मलेशिया है। बता दें कि घरेलू हवाई किराए में बढ़ोतरी को लेकर एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल (एसीआई) की रिपोर्ट से जानकारी मिली है। ये काउंसिल फ्लेयर एविएशन कंसल्टिंग के सहयोग से कुल 617 हवाई अड्डों का प्रतिनिधित्व करता है। बता दें कि इस बार एसीआई बोर्ड की बैठक सोमवार को ही हुई है जिसमें चर्चा इस रिपोर्ट पर की गई है। इस रिपोर्ट की मानें तो दुनिया के कुल 19 देशों में 60,000 से अधिक मार्गों पर हवाई किराए का विश्लेषण किया गया है। इससे क्षेत्र में महामारी के बाद की स्थिति में सुधार के बारे में भी पता चला है। घरेलू स्तर पर सबसे अधिक किराए में बढ़ोतरी वियतनाम में हुई है। इसके बाद सर्वाधिक वृद्धि भारत में हुई है। अन्य देश जहां घरेलू किराया बढ़ाया गया है उसमें मलेशिया (36 प्रतिशत), थाईलैंड (26 प्रतिशत) और

ऑस्ट्रेलिया (21 प्रतिशत) शामिल हैं। किराया बढ़ोतरी अधिकतर उन देशों में हुई है जहां घरेलू मांग अधिक है। अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर गौर करें तो भारत और वियतनाम दोनों देशों ने हवाई किराए में 16 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की है। वहीं सबसे अधिक बढ़ोतरी यूएई ने की है जो 22 प्रतिशत है। इसके बाद दूसरे नंबर पर मलेशिया है जिसने 21 फीसदी का इजाफा किया है। वहीं भारत और वियतनाम के बाद ऑस्ट्रेलिया (14 प्रतिशत) और थाईलैंड (7 प्रतिशत) की बढ़ोतरी करने में शामिल है। एसीआई एपीएसी और मध्य पूर्व के महानिदेशक स्टेफानो बैरोनसी की मानें तो इस वर्ष यात्रियों की संख्या महामारी से पहले के स्तर पर लौटती दिख रही है। कई यात्री अधिक भुगतान करने में भी पीछे नहीं है। इससे पता चलता है कि हवाई यात्रा की मांग 2019 की तुलना में अधिक हो सकती है। ऐसे में ये सुनिश्चित करना चाहिए की किराए में होने वाली बढ़ोतरी ग्राहकों के लिए परेशानी ना बने। बैरोनसी का कहना है कि एयरलाइनों द्वारा निर्धारित जटिल मूल्य निर्धारण प्रणाली से प्रभावित होकर ही हवाई किराया तय होता है। वहीं हवाईअड्डे के शुल्क हवाई किराए में वृद्धि का कारण नहीं हैं। हवाईअड्डे के शुल्क समय के साथ अपेक्षाकृत स्थिर रहे हैं, जो एयरलाइनों की परिचालन लागत का लगभग 4 प्रतिशत है।

■ इस संबंध में बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट की मानें तो इस समयसीमा के दौरान अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा के किराए में बढ़ोतरी करने के मामले में भारत के बाद संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और मलेशिया है। घरेलू हवाई किराए में बढ़ोतरी को लेकर एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल (एसीआई) की रिपोर्ट से जानकारी मिली है।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA
Corporate Communications Directorate

MINT DELHI 8 NOVEMBER 2024

Passing of Jet bares limits of bankruptcy framework

Krishna Yadav
krishna.yadav@livemint.com
NEW DELHI

The Supreme Court's decision ordering the liquidation of Jet Airways, once India's leading airline, has provided sufficient fodder for bankruptcy experts seeking an overhaul of India's insolvency framework.

The liquidation comes at the end of years of dispute between the airline's winning consortium and its lenders that played out in courts.

Justice J.B. Pardiwala, who pronounced the ruling, remarked that this case served as an eye-opener for the functioning of insolvency tribunals and for India's Insolvency and Bankruptcy Code.

The liquidation raises broader questions about the effectiveness of the IBC framework in handling airline insolvencies, especially since lenders to Go First have also voted for liquidation after a failed attempt to revive it.

"Airline insolvencies pose issues that are quite unique and an approach that works in other sectors may not necessarily work with airline insolvencies," said Vihang Virkar, part

TURN TO PAGE 6

Passing of Jet Airways bares limits of bankruptcy framework

FROM PAGE 1

ner, DMD Advocates.

"Airlines in India typically do not own most of their fleet and the ownership lies with the aircraft lessors. The only assets of value in an airline are, therefore, its landing-parking rights, slots, people, and low-value ground-handling and engineering equipment," he added. "None of these can be easily converted to liquid funds in the case of a liquidation."

The Supreme Court ordered the liquidation after finding that the Jalan Kalrock Consortium (JKC) had failed to comply with the conditions of its resolution plan, marking the final chapter in Jet's long struggle for revival.

The court concluded that liquidation was the only viable option through which creditors could recover some of their dues.

"I hope this judgment leads to changes in the IBC framework, with amendments to address insolvencies in the aviation sector," Virkar added.

Sumant Nayak, senior partner at Desai & Diwanji law firm, termed it a defining case for the entire IBC framework. "These are watershed moments in the landscape of insolvency and resolution process and it may spur development of guidelines towards setting up of soft timelines for implementation of the resolution plan."

Jet Airways suspended its operations in April 2019. HT

"We are satisfied with the outcome. JKC's repeated non-compliance with the terms of the resolution plan caused the value of the plan to diminish significantly," said Devesh Dubey, senior associate at Sanjay RPK Law, a firm representing Jet Airways's lenders. "The Hon'ble Supreme Court has correctly concluded that liquidation is the appropriate course of action."

Jet Airways, founded by Naresh Goyal, suspended its flight operations in April 2019 due to financial troubles.

The Supreme Court, as part of its order on Thursday, set aside the National Company Law Appellate Tribunal's March decision upholding the transfer of ownership of Jet Airways to JKC.

It criticized the NCLAT for disregarding its previous rulings and for allowing the order in favour of JKC without fully examining the facts.

The lenders had argued that JKC's resolution plan was "unworkable" and urged the court to use its inherent powers under Article 142 to liquidate the airline.

Jet Airways's former accountable manager Captain P. P. Singh said the Supreme Court ruling was on expected lines as there was no visible sign that JKC was technically and financially capable of reviving and successfully operating an airline like Jet.

"They bid for the airline without understanding the intricacies of the business, thinking they could somehow make it work. But with no real experience in aviation, they didn't stand a chance of successfully implementing the complex resolution plan," Singh said.

He added that the likelihood of Jet Airways going into liquidation was a possibility right from the beginning given how the resolution plan was written. "The plan was doomed to fail because of its own inherent flaws," Singh said, while also criticizing Jet's resolution professional for failing to protect the airline's assets, he said.

Scan the QR code to read an extended version of this story.

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

Corporate Communications Directorate

MILLENNIUM POST DELHI 8 NOVEMBER 2024

SC orders liquidation of Jet Airways assets

Forfeiture of winning bidder's money

OUR CORRESPONDENT

NEW DELHI: In a major development in the Jet Airways insolvency saga, the Supreme Court on Thursday ordered the grounded airline's liquidation, forfeiture of Rs 200 crore infused by successful bidder Jalan Kalrock Consortium.

The apex court also permitted the lenders led by SBI to encash Rs 150 crore performance bank guarantee.

Invoking its extraordinary powers under Article 142 of the Constitution, a bench comprising Chief Justice D Y Chandrachud and Justices J B Pardiwala and Manoj Misra put the curtains down on the insolvency proceedings of the airlines by setting aside the order of the National Company Law Appellate Tribunal (NCLAT).

The bench termed the case as an "eye opener" and rapped NCLAT for allowing adjustment of performance bank guarantee (PBG) in view of payment Continued on P4

Takeaways

- The apex court also permitted the lenders led by SBI to encash Rs 150 crore performance bank guarantee
- Invoking its extraordinary powers under Article 142 of the Constitution, a bench comprising Chief Justice D Y Chandrachud and Justices J B Pardiwala and Manoj Misra put the curtains down on the insolvency proceedings of the airlines by setting aside the order of the NCLAT

SC orders liquidation of Jet Airways assets

Continued from Page 1

Of the first tranche by Jalan Kalrock Consortium (JKC).

Insolvency appellate tribunal NCLAT had allowed JKC to take over Jet Airways without fully complying with its payment obligations, it observed.

"The impugned order of the NCLAT directing the SRA (successful resolution applicant) to adjust PBG of Rs 150 crore against first tranche of payment of Rs 350 crore was in flagrant disregard of the order of this court…," it said.

Pronouncing judgement for the bench, Justice Pardiwala allowed the plea of SBI and other creditors against the NCLAT decision that upheld the resolution plan of Jet Airways in favour of JKC.

The apex court, as a result, allowed the appeals of the lenders and set aside the NCLAT order."In the peculiar and alarming circumstances as discussed in this judgement, and also keeping in mind the fact that almost five years have elapsed since the resolution plan was duly approved by the NCLT (National Company Law Tribunal) and there being no progress worth the name, we are left with no other option but to invoke our jurisdiction under Article 142 of the Constitution and direct to the corporate debtor be taken in liquidation," held the bench.

Article 142 of the Constitution gives top court the power to make orders and decrees to ensure complete justice in any matter or cause pending before it.The bench ordered that requisite steps be taken for commencement of liquidation process of the grounded airline and "the amount of Rs 200 crore already infused by the SRA stands forfeited".

"The lender creditors are further permitted to encash the performance bank guarantee of Rs 150 crores furnished by the SRA," it added.

It held that the NCLAT's approval of adjusting the performance bank guarantee as a partial payment was in "flagrant disregard" of an earlier directive of the top court, as well as the terms of the resolution plan and established principles under the Insolvency and Bankruptcy Code.

It noted in addition to nonpayment of the initial tranche, JKC, represented by advocates Debmalya Banerjee and Kartik Bhatnagar of Karanjawala & Co., had not cleared other crucial dues, including corporate insolvency resolution process costs and employee dues.

"The litigation has been an eye-opener on multiple issues, including NCLAT's functioning," Justice Pardiwala noted, stressing that JKC's failure to implement the resolution plan triggered provisions of the IBC that necessitate liquidation.

It emphasised that timely compliance with resolution plans is fundamental to the IBC's purpose, which prioritises swift and effective resolution for distressed companies.

"We have no doubt in our mind that the NCLAT acted contrary to the settled legal principles and went to the extent of drawing wrong inferences from true facts while deciding the matter," it said.

On the first issue, the top court concluded that the performance bank guarantee of Rs 150 crore could not have been adjusted against the first tranche payment of Rs 350 crore, which was to be made by the SRA under the resolution plans."The IBC is clear in its intention that PBG shall not be set off or used as a part of the consideration that was to be given by the SRA under the plan," it said.

"We arrived at the findings that this SRA failed to implement the resolution plan by not depositing the first tranche of payment…," it said.

The NCLAT on March 12 upheld the resolution plan of the grounded air carrier and approved the transfer of its ownership to JKC. The SBI, Punjab National Bank and JC Flowers Asset Reconstruction Private Limited challenged the NCLAT verdict.

The appellate tribunal had further directed the Jet Airways monitoring committee to complete the transfer of ownership within 90 days. Besides, the NCLAT had also directed the lenders of Jet Airways to adjust Rs 150 crore paid by the consortium as performance bank guarantee.The banks had said the JKC failed to meet its financial obligations, including the infusion of Rs 350 crore within the stipulated 180-day period from the effective date under the resolution plan.Jet Airways, which has remained grounded since April 2019, had in September, 2023 said the new proposed promoters -- the Jalan-Kalrock consortium -- had completed an additional infusion of Rs 100 crore into the carrier.The airline had also said it was looking to re-launch operations from 2024.

After grounding in 2019 owing to a severe liquidity crisis at that time, the full-service carrier underwent an insolvency resolution process.

However, it was having a dispute with the lender. In 2021, JKC emerged as the successful bidder of Jet Airways.

WITH AGENCY INPUTS

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA
Corporate Communications Directorate

THE MORNING STANDARD DELHI 8 NOVEMBER 2024

Jet liquidation flight rostered as SC claims there's no alternative

Orders forfeiture of Jalan-Kalrock consortium's ₹200 cr

ARSHAD KHAN @ New Delhi

THE Supreme Court on Thursday dashed all hopes of a revival of Jet Airways as it ordered liquidation of the firm, which had been undergoing the insolvency resolution process for over five years. A bench of Chief Justice D Y Chandrachud and Justices J B Pardiwala and Manoj Misra set aside the National Company Law Appellate Tribunal (NCLAT) ruling that upheld the transfer of the airline's ownership to Jalan-Kalrock Consortium (JKC).

The bench stated that the liquidation was in the interest of creditors, workers, and other stakeholders of Jet Airways. The court noted JKC's failure to infuse the promised funds of ₹350 crore to revive the cash-strapped airline.

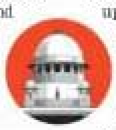

The SC said no progress was seen the resolution plan even after five years, leaving it with no choice but to send Jet Airways into liquidation. "Keeping in mind the fact that almost five years have elapsed since the Resolution Plan was duly approved by the NCLAT and there being no progress worth the name, we are left with no other option but to invoke our jurisdiction under Article 142 of the Constitution and direct that the corporate debtor be taken in liquidation," it said in the order.

The SC held the NCLAT's directive for the SRA to adjust ₹150 crore towards the first tranche payment was in disregard of the Supreme Court's earlier order and the terms of the resolution plan.

The bench also ordered forfeiture of ₹200 crore invested by the consortium and authorised the lenders to invoke the ₹150 crore bank guarantee to recover some of their dues.

The NCLAT had in March upheld the resolution plan of Jet Airways and approved the transfer of its ownership to JKC. SBI, Punjab National Bank, and JC Flowers Asset Reconstruction Pvt Ltd challenged the NCLAT verdict.

Jet Airways stopped flying in April 2019. The National Company Law Tribunal in June 2021 gave approval to the Kalrock Capital and Murari Lal Jalan consortium's bid for Jet Airways, eight months after the lenders had given a go-ahead to its resolution plan.

The consortium was supposed to infuse ₹1,375 crore in Jet Airways over 2-3 years. In the first tranche, it was to infuse ₹350 crore and ₹250 crore in the second tranche. The remaining ₹775 crore was to be infused from the second year. However, the consortium put in only ₹200 crore.

'NCLAT ORDER PERVERSE'

The Supreme Court rapped the NCLAT for allowing the Jalan-Kalrock Consortium to take over Jet Airways without fulfilling its payment obligations, terming the Appellate Tribunal's verdict 'perverse'

PAYMENT NORMS FLOUTED

SC noted that the NCLAT's approval of adjusting the performance bank guarantee as a partial payment was in "flagrant disregard" of an earlier directive of the court, as well as the terms of the resolution plan

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA
Corporate Communications Directorate

NAVBHARAT TIMES DELHI 8 NOVEMBER 2024

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में NCLAT के फैसले को पलट दिया

जेट की संपत्तियां बिक जाएंगी, SC का आदेश

AI Image

■ विस, नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बंद पड़ी एयरलाइन जेट एयरवेज के लिक्विडेशन का आदेश दे दिया है। कोर्ट का कहना है कि इस मामले में एनसीएलएटी का फैसला शीर्ष अदालत के जनवरी 2023 के फैसले की घोर अवहेलना है।

NBT Explainer

Q क्या है मामला?

नरेश गोयल के नेतृत्व वाली एयरलाइन कभी भारत की प्रमुख एयरलाइन थी। लेकिन 2019 से ही इसका परिचालन बंद है। एनसीएलएटी ने जेट का मालिकाना हक यूके की कंपनी कालरॉक कैपिटल और संयुक्त अरब अमीरात के कारोबारी मुरारी लाल जालान के कंसोर्टियम को ट्रांसफर करने को मंजूरी दी थी।

Q सुप्रीम कोर्ट क्यों खफा?

कोर्ट के मुताबिक एनसीएलएटी ने जेट एयरवेज के रेजॉल्यूशन एप्लिकेंट जालान-कालरॉक कंसोर्टियम की 150 करोड़ रुपये की परफॉरमेंस बैंक गारंटी के समायोजन की अनुमति देकर कोर्ट के जनवरी 2023 के आदेश की अवहेलना की है। समाधान प्रस्ताव के मुताबिक एयरलाइन में 350 करोड़ के निवेश की जरूरत थी। एनसीएलएटी ने परफॉरमेंस बैंक गारंटी को इसके अगेंस्ट अडजस्ट करने की अनुमति दी थी।

Q बैंकों की दलील क्या थी?

सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में SBI समेत कई बैंकों का कहना था कि यह कंसोर्टियम एयरलाइन के अधिग्रहण के लिए तय की गई शर्तों को पूरा करने में विफल रहा। अब एयरलाइन को रिवाइव करने की स्थिति में नहीं है। नरेश गोयल ने जेट एयरवेज इंडिया लिमिटेड की शुरुआत कर लोगों को एअर इंडिया का ऑल्टरनेटिव दिया था। एक वक्त जेट के पास कुल 120 प्लेन थे और वो लीडिंग एयरलाइन में से एक हुआ करती थी।

Q क्यों लिया यह फैसला?

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि लिक्विडेशन इसके लोन देने वाले और कर्मचारियों के सर्वोत्तम हित में होगा, क्योंकि जालान-कालरॉक कंसोर्टियम मंजूरी के पांच साल बाद भी समाधान योजना को लागू करने में विफल रहा है। सबसे ज्यादा लोन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने दिया था। एयरलाइन के घाटे में जाने के बाद बैंकों ने दिवालिया की कार्रवाई शुरू की थी। समाधान योजना के तहत JKC को मालिकाना हक मिलना था। एसबीआई, पीएनबी और अन्य ने एनसीएलएटी के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA
Corporate Communications Directorate

THE PIONEER DELHI 8 NOVEMBER 2024

Supreme Court orders liquidation of grounded Jet Airways' assets

PIONEER NEWS SERVICE
NEW DELHI

The Supreme Court (SC) on Thursday exercised its extraordinary constitutional powers and ordered the liquidation of grounded air carrier Jet Airways' assets.

A bench of Chief Justice DY Chandrachud and Justices JB Pardiwala and Manoj Misra set aside the National Company Law Appellate Tribunal (NCLAT) decision upholding the resolution plan of Jet Airways, which approved the transfer of its ownership to Jalan Kalrock Consortium (JKC).

Pronouncing the judgement for the bench, Justice Pardiwala allowed the plea of the State Bank of India (SBI) and other creditors against the NCLAT decision that upheld the resolution plan of Jet Airways in favour of JKC. It said the liquidation of the air carrier was in the interest of creditors, workers and other stakeholders.

The bench came down on the NCLAT, which the SC held disregarded the court's 2023 ruling.

"We have no doubt that the NCLAT acted contrary to settled legal principles... NCLAT incorrectly interpreted our order," the court noted in the judgment. The fundamental concern is not only to do substantial justice but also to bring speedy disposal of dispute, it further noted.

The court used its powers under Article 142 of the Constitution which gives it the power to make orders and decrees to ensure complete justice in any matter or cause pending before it.

The NCLAT on March 12 upheld the resolution plan of the grounded air carrier and approved the transfer of its ownership to JKC. The SBI, Punjab National Bank (PNB) and JC Flowers Asset Reconstruction Private Limited had challenged the NCLAT verdict.

Additional Solicitor General (ASG) N Venkataraman appeared for the SBI- the lead lender of Jet Airways, while Senior Advocates Mukul Rohatgi and Gopal Sankaranarayanan represented the Successful Resolution Applicant (SRA) Jalan KalRock Consortium (JKC). In the past, Jet was the second largest carrier in India.

RASHTRIYA SAHARA DELHI 8 NOVEMBER 2024

जेट एयरवेज अब कभी नहीं भर पाएगी उड़ान

■ पांच साल से ठप एयरलाइन का होगा परिसमापन

■ नकदी संकट के चलते एयरलाइन ने परिचालन बंद किया था

नई दिल्ली (भाषा)। जेट एयरवेज ने 25 साल तक पूर्ण सेवा एयरलाइन के रूप में उड़ान भरने के बाद पांच साल पहले अप्रैल के महीने में अस्थायी रूप से अपना परिचालन बंद करने की घोषणा की थी। नकदी संकट की वजह से एयरलाइन ने यह कदम उठाया था। अब उच्चतम न्यायालय के एयरलाइन के परिसमापन के आदेश के बाद इसके फिर से उड़ान भरने की संभावना पूरी तरह समाप्त हो गई है।

एयरलाइन का परिचालन ठप होने के बाद से करीब 20,000 से अधिक नौकरियां जा चुकी है और ऋणदाताओं, विक्रेताओं और यात्रियों का हजारों करोड़ रुपये का बकाया दिवाला समाधान की प्रतीक्षा में 'डूब' गया है। बृहस्पतिवार को सर्वोच्च न्यायालय ने एयरलाइन के परिसमापन का आदेश दे दिया, जिससे एयरलाइन के अस्त-व्यस्त सफर का औपचारिक समापन हो गया तथा पुनरुद्धार की उम्मीदें भी चकनाचूर हो गईं।

एयरलाइन की आखिरी उड़ान एस2-3502 अमृतसर से 17 अप्रैल, 2019 को रात करीब 10.30 बजे रवाना हुई और 18 अप्रैल को तड़के 12.22 बजे मुंबई के छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरी। जेट एयरवेज की किफायती इकाई जेटलाइट ने बोइंग 737-800 विमान के साथ उड़ानों का संचालन किया, जिसे बाद में किफायती एयरलाइन स्पाइसजेट ने पट्टे पर ले लिया। अपने परिचालन के चरम के दौरान जेट एयरवेज के पास 120 से ज्यादा विमान थे। बढ़ते कर्ज और कर्मचारियों का वेतन भुगतान नहीं होने के चलते जब एयरलाइन ने परिचालन बंद किया था तो उसके पास अपने खुद के 16 विमान थे। नरेश गोयल द्वारा स्थापित इस एयरलाइन ने ढाई दशक से अधिक समय तक करोड़ों यात्रियों को सेवा प्रदान की है। गोयल ने यात्रा एजेंसी जेटएयर के साथ कई अंतरराष्ट्रीय एयरलाइन के लिए एक सामान्य बिक्री एजेंट के रूप में शुरुआत की थी। जेट एयरवेज भी भारतीय विमानन क्षेत्र में प्रमुख निजी एयरलाइन में से एक थी, लेकिन वित्तीय संकट के कारण इसका पतन शुरू हो गया।

एयरलाइन ने अपनी यात्रा एक एयर टैक्सी परिचालक के रूप में मुंबई से अहमदाबाद तक सेवा के साथ शुरू की थी। अपने चरम पर इसमें लगभग 1,300 पायलट समेत लगभग 20,000 कर्मचारी थे। साल 2019 में परिचालन को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा के समय जेट एयरवेज के पास 20,000 से अधिक कर्मचारी थे। उस समय कंपनी पर बैंकों का 8,500 करोड़ रुपये से अधिक बकाया था। इसके अलावा एजेंट और यात्री रिफंड के हजारों करोड़ रुपये बकाया थे।

जेट एयरवेज द्वारा 17 अप्रैल, 2019 को परिचालन बंद करने के कुछ सप्ताह बाद ऋणदाताओं ने अपना बकाया वसूलने के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया की मांग की। राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने 20 जून, 2019 को एयरलाइन के खिलाफ दायर दिवाला याचिका को स्वीकार कर लिया। जालान कलरॉक गठजोड़ (जेकेसी) 2021 में दिवाला समाधान प्रक्रिया के तहत जेट एयरवेज के सफल बोलीदाता के रूप में उभरा, लेकिन ऋणदाताओं के साथ लगातार मतभेदों के परिणामस्वरूप समाधान योजना धरी की धरी रह गई।

बृहस्पतिवार को सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी असाधारण शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) के आदेश को रद्द करते हुए एयरलाइन की दिवाला कार्यवाही पर रोक लगा दी। एनसीएलएटी ने कहा कि उसने भुगतान दायित्वों का पूर्णतः पालन किए बिना ही जेकेसी को जेट एयरवेज का अधिग्रहण करने की अनुमति दे दी थी। परिसमापन के अलावा, सर्वोच्च न्यायालय ने सफल बोलीदाता जेकेसी द्वारा डाले गए 200 करोड़ रुपये जब्त करने का निर्देश दिया है।

न्यायालय ने एसबीआई के नेतृत्व वाले ऋणदाताओं को 150 करोड़ रुपये की निष्पादन बैंक गारंटी भुनाने की भी अनुमति दी है। अदालत ने एनसीएलएटी के फैसले के खिलाफ एसबीआई और अन्य ऋणदाताओं की याचिका को स्वीकार कर लिया। एनसीएलएटी ने जेकेसी के पक्ष में जेट एयरवेज की समाधान योजना को बरकरार रखा था। एयरलाइन के ठप होने के इतने वर्षों के बाद जो कुछ बचा है वह है... बाधित आजीविका, बकाया राशि का भुगतान न होना और धूल खाते हुए जेट एयरवेज की छवि वाले कुछ विमान...।

RASHTRIYA SAHARA DELHI 8 NOVEMBER 2024

उड़ान के दो बार रद्द होने पर यात्रियों ने किया प्रदर्शन

भुवनेश्वर। हैदराबाद के लिए निर्धारित एक उड़ान के दो बार रद्द होने को लेकर कई यात्रियों ने बृहस्पतिवार को यहां बीजू पटनायक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (बीपीआईए) पर विरोध प्रदर्शन किया। कई यात्रियों ने दावा किया कि उड़ान रद्द होने के कारण उनके निर्धारित कार्यक्रम बाधित हुए हैं। प्रदर्शनकारी यात्रियों के अनुसार, एक निजी विमानन कंपनी द्वारा भुवनेश्वर से हैदराबाद के लिए संचालित उनकी उड़ान बुधवार को रद्द कर दी गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें बताया गया था कि बृहस्पतिवार को उड़ान का समय पुनर्निर्धारित किया गया है, लेकिन इसे फिर से रद्द कर दिया गया, जिससे उन्हें असुविधा हुई। यात्रियों ने यह भी आरोप लगाया कि हवाई अड्डे के अधिकारियों ने उन्हें उड़ान रद्द होने के संबंध में किसी विशेष कारण के बारे में सूचित नहीं किया है।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA
Corporate Communications Directorate

THE TELEGRAPH KOLKATA 7 NOVEMBER 2024

SpiceJet AGM by December

NEW DELHI: SpiceJet on Wednesday said the AGM for 2023-24 will be held on or before December 31 as the company has been given up to three more months to conduct the meeting. The crisis-hit carrier said it had received emails from the BSE regarding the non-submission of the annual report for March 31, 2024. PTI

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA
Corporate Communications Directorate

THE TIMES OF INDIA   DELHI   8 NOVEMBER 2024

End of runway for Jet: SC orders liquidation, nixes revival plan

Allows Lenders' Consortium To Forfeit JKC's ₹350cr

Dhananjay.Mahapatra
@timesofindia.com

New Delhi: Hopes of Jet Airways getting fresh wings crashed on Thursday as the Supreme Court ordered its liquidation, with the successful bidder — Jalan Kalrock Consortium — failing to deposit even the first tranche of Rs 350 crore of the Rs 4,783 crore resolution plan for years, thereby burdening SBI-led lenders with huge financial liabilities.

Noting the gross violations of the plan by JKC, comprising UAE-based NRI Murari Lal Jalan and Florian Fritsch, who holds shares in Jet Airways through his Cayman Islands-based investment holding company Kalrock Capital Partners, the SC exercised its rarely-exercised omnibus powers under Article 142 of the Constitution to order liquidation of the unviable airline.

In a 169-page judgment which provided guidelines for future Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) proceedings and streamlining the processes before company law tribunals NCLT and NCLAT, the bench accepted arguments of additional solicitor general N Venkataraman and SBI counsel Sanjay Kapur to allow SBI-led lenders' consortium to forfeit the Rs 250 crore deposited by JKC as well as its Rs 150-crore performance bank guarantee.

> Amount of ₹200cr already infused by SRA (successful resolution applicant in JKC) stands forfeited. Lenders/creditors are further permitted to encash performance bank guarantee of ₹150cr furnished by SRA —SC

▶ EDIT: Grounded
▶SC lets customs revive notices for ₹20k cr duty, P13

▶No option, P 22

No option but to order liquidation, says SC after no progress in Jet revival plan

▶ Continued from P 1

Writing the judgment for the bench, Justice Pardiwala said, "The amount of Rs 200 crore already infused by SRA (successful resolution applicant in JKC) stands forfeited. Lenders/creditors are further permitted to encash the performance bank guarantee of Rs 150 crore furnished by SRA. We order accordingly."

The bench said, "In the peculiar and alarming circumstances as discussed in this judgment and keeping in mind the fact that almost five years have elapsed since Resolution Plan was duly approved by NCLAT and there being no progress worth the name, we are left with no other option but to invoke our jurisdiction under Article 142 of the Constitution and direct that Jet Airways be taken in liquidation. The NCLT, Mumbai, shall now take appropriate steps for appointment of liquidator and all other necessary formalities for commencement of liquidation of Jet Airways."

Faulting NCLAT for allowing JKC to adjust performance bank guarantee of Rs 150 crore to meet the shortfall in deposit of first tranche of Rs 350 crore which was to be made good by May 22, 2022, the bench said for five years, the resolution plan remained in limbo during which period several dues, including airport dues, to be paid by Jet Airways have increased due to the fault of JKC. "The court must ensure that such debts stop running at some point of time," it said.

The bench said although IBC was enacted to ensure survival of bankrupt entities, the same must not come at the cost of efficiency. "In scenarios such as the present, 'timely liquidation' is indeed preferred over an 'endless resolution process'," it said. "Such a view will prevent the likelihood of adversely affecting interests of all creditors who have been suffering due to no fault of their own and securing the maximisation of value of the remaining assets," the court said.

Rejecting pleas of senior advocates Mukul Rohatgi and Gopal Sankaranarayanan, who appeared for JKC and blamed SBI-led consortium of non-cooperation while seeking more time to fully pay the first tranche, the bench said, "No further extensions or accommodations can be given to JKC in light of multiple opportunities already granted."

Terming JKC case an eye-opener for the IBC platform, Justice Pardiwala said, "Scrupulous following of the code along with behavioural and ethical discipline is especially required from key participants of IBC who are central to its design, that is the adjudicating authorities, corporate debtors, resolution professionals, committee of creditors, potential and successful SRAs, approved valuers, and liquidators."

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA
Corporate Communications Directorate

THE TIMES OF INDIA DELHI 8 NOVEMBER 2024

Grounded, By Process

Jet Airways case is a reminder India can't afford to have bankruptcy procedures drag on for years

As Supreme Court calls it curtains on Jet Airways, it's another tragic tale of another short-lived star business and the challenges of sustaining airline ops in a competitive, high-cost environment. But the real concern is a larger issue – the process that culminated in the liquidation of Jet Airways is reminder again of how broken India's bankruptcy resolution efforts are.

The Focus | SC commented the litigation was an "eye-opener" as it swung its attention on NCLT, the adjudicating authority for corporate disputes, and IBC, the 2016 insolvency and bankruptcy code that has seen six rounds of amendments and a further round expected in Parliament soon. NCLT's record has been poorer than poor – messy pile-ups of cases, paucity of capability and capacity, legal imbroglios, and failure to inspire confidence among business communities, simply given the vacancies. The Jet Airways case is also a commentary on GOI's intent on firming up the framework to free up capital.

The Case | At the crux of the case SC decided was SBI-led lenders' appeal against NCLT's go-ahead for Jet Airways to be transferred to Jalan-Kalrock Consortium that had successfully bid for the carrier in 2021, as part of NCLT's resolution process in 2019. SBI, as Jet's main lender, had sought the carrier's liquidation. But the bidder failed to meet key financial commitments, leading lenders to incur ongoing costs. SC yesterday overruled NCLT's go-ahead – five years since SBI moved NCLT.

The Law | IBC was intended to streamline insolvency processes and enhance credit flow. But a high proportion of cases end in liquidation, not resolution. Legal challenges further hobble processes. But the most damaging to India's business environment is the lengthy resolution process. The Jet Airways case dragged a full GOI term, instead of being resolved within 180 days, as the law mandates, extendable by 90 days. IBC itself needs resolution – a poorly implemented law can barely help sinking businesses.